संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

दैनिक घटती घटना

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050
Postal Reg.No.-13/Surguja DN/2023-2025

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर,वर्ष 19,अंक -281 शनिवार , 12 अगस्त 2023,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

लोकसभा में पेश किए गए तीन बिल

» नाबालिग से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग पर सजा-ऐ-मौत

» पीसी-सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदला जाएगा,

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया

नई दिल्ली,11अगस्त 2023(ए)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किए। अमित शाह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023, इन तीनों बिलों को स्क्रूटनी के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। उक्त बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पीनल कोड , कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। निम्नांकित तीनों बिल संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किया है। बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजे जाने की बात गृहमंत्री ने की है। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं।

इन नए 9 बिंदुओं वाले बिल से क्या बदलाव

» आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

» मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।

» सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर अनुमति देनी होगी।

» दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान लाया गया है।

» जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना जरूरी होगा।

» अलगाववादी गतिविधियों,सशस्त्र विद्रोह,देश की संप्रभुता,एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को लिस्ट किया जाएगा।

» महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

» आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है।

» गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

पीएम मोदी मणिपुर की आग नहीं बुझाना चाहते

नई दिल्ली,11अगस्त 2023(ए)। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन दिए गए भाषण के बाद से पूरे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी ने अपने दो घंटे 13 मिनट के भाषण में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में अंत में मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट की। इन 2 मिनट में भी पीएम हंसकर मणिपुर का मजाक उड़ा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना 2 दिनों में इस पूरी हिंसा को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन पीएम ने आग बुझाने से मना किया। पीएम आग बुझाना ही नहीं चाहते वे तो खुद मणिपुर को जलाना चाहते है।

पहली बार 2 देशों के चंद्रयान एक साथ चंद्रमा पर करेंगे लैंड

नई दिल्ली,11अगस्त 2023(ए)। इस साल दुनिया के लिए 23 अगस्त की तारीख बहुत खास होने जा रही है। इसी दिन पहली बार 2 देशों के अंतरिक्ष यान एक साथ चंद्रमा के दक्षिण छोर पर लैंड करेंगे। चंद्रमा के इस छोर पर अभी तक किसी भी देश का अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा है जो दोनों देश यह उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, उनके नाम हैं भारत और रूस। भारत ने पिछले साल भी चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजा था लेकिन तब

उसे सफलता नहीं मिल पाई थी।

रूस भी चंद्रमा पर भेजेगा अंतरिक्ष यान

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस लगभग 50 वर्ष आज चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान रवाना करेगा। उसने वर्ष 1976 के बाद आज तक चंद्रमा पर कोई मिशन नहीं भेजा है। वह आज चंद्रमा पर अपने 'लूना-25' यान को भेजेगा। इस यान का प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद के बिना किया जाएगा। उसने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मॉस्को के साथ अपना सहयोग समाप्त कर दिया है।

किस वजह से मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया

नई दिल्ली,11अगस्त 2023(ए)। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन से अपने सस्पेंशन के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। राघव ने एक वीडियो जारी करते हुए सवाल किया है कि मेरा अपराध क्या है, जिस वजह से मुझे सस्पेंड किया गया? राघव ने कहा, 'नमस्कार! मैं सस्पेंडेड सांसद राघव चड्ढा.. मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा क्या अपराध है। क्या मेरा ये अपराध है कि, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं से पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल पूछ लिया?' राघव ने आगे कहा कि, 'क्या मेरा ये अपराध है कि, मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग की? उन्हें उन्हीं का पुराना घोषणा पत्र दिखाकर वादे पूरा करने को कहा? बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को आदवाणी वादी और बाजपेयी वादी होने की बात कही। क्या इन्हें ये डर सताता है कि कैसे एक 34 साल युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है। '

'मैं चुनौतियों से डरने वाला नहीं हूं'

राघव ने कहा, ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।

संपादकीय

मणिपुर में बिगड़ते हालात

मणिपुर में हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां की पुलिस कथित तौर पर सिर्फ मैतई समुदाय के संरक्षक बल के रूप में काम कर रही है। ऐसे में उसकी निगाह में अर्धसैनिक दस्तों का अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के लोगों को संरक्षण देना अपराध बन गया है।

मणिपुर में अशांति की शुरुआत हुए तीन महीना गुजर गए हैं, लेकिन आज भी हर रोज आने वाली खबर वहां लगातार बिगड़ रहे हालात का संकेत दे रहे हैं। अब तक बात दो समुदायों के बीच हो रही हिंसा की थी। लेकिन अब झगड़ा राज्य पुलिस और एक अर्ध सैनिक बल के बीच तक पहुंच गया है। पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के जवान आपस में तू तू-मैं मैं करते देखे गए। फिर खबर आई कि असम सरकार ने चूराचांदपुर और विष्णुपुर के बीच मौजूद एक चौकी से असम राइफल्स की टुकड़ी को हटने का आदेश दिया। अब खबर आई है कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है। इसमें असम राइफल्स पर कुकी चरमपंथियों को भागने का मौका देने और उन्हें संरक्षण देने का इल्जाम लगाया गया है। यहां इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है कि असम राइफल्स की कमान भारतीय सेना के पास है।

क्या बात किसी आम कल्पना में समा सकती है कि भारतीय सेना उग्रवादियों की मदद कर रही है? लेकिन मणिपुर में हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां पुलिस कथित तौर पर सिर्फ मैतई समुदाय के संरक्षक बल के रूप में काम कर रही है। ऐसे में उसकी निगाह में संभवतः अर्धसैनिक दस्तों का अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के लोगों को संरक्षण देना अपराध बन गया है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इस पर तुरंत नियंत्रण कायम नहीं किया गया, तो स्थितियां हमारी आशंकाओं से भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। यह अच्छी बात है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से देश का ध्यान मणिपुर के हालात पर टिका है। विपक्षी नेताओं ने वहां की स्थितियों का विस्तार वर्णन कर देश को इस बारे में आगाह किया है। अब अपेक्षित है कि जब प्रधानमंत्री जब जवाब दें, तो वे इस दौरान उठे गंभीर प्रश्नों के ठोस उत्तर प्रस्तुत करें। उससे मणिपुर में स्थितियों को बेहतर करने में मदद मिलेगी और सारे देश में भरोसा पैदा होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, तो फिर अविश्वास का माहौल और गहरा जाएगा।

बिना चर्चा के विधेयक पास होने के खतरे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय वित्त व गृह मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने छह अगस्त को अखबार के अपने साप्ताहिक स्तंभ में 'लेजिस्लेटिंग ऑथोरिटेरियनिज्म' शीर्षक से लेख लिखा। इस शीर्षक का मोटा-मोटी अनुवाद यह है कि अधिनायकवाद को विधायी रूप देना या विधायी अधिनायकवाद। उन्होंने अपने लेख में संसद में पेश हुए या पास हुए तीन विधेयकों का जिक्र किया।उन्होने बताया कि कैसे इन विधेयकों के जरिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानूनी रूप से सही नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ तीन विधेयकों का जिक्र किया लेकिन इनके अलावा भी कई विधेयक हैं, जिनसे केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार छीन रही है, संघवाद की अवधारणा को चोट पहुंचा रही है और लोगों के निजता के अधिकार को भी चोट पहुंचा रही है। सरकार ने जिस मनमाने तरीके से ये विधेयक तैयार किए और जिस अंदाज में इसे पास कराया उससे देश की संघीय और संवैधानिक व्यवस्था के सामने जैसी चुनौतियां पैदा हुई हैं उनके बारे में चिदंबरम ने लिखा है। लेकिन सवाल है कि जो बातें उन्होंने लेख में लिखी हैं, वह बात उन्होंने संसद में क्यों नहीं कही? उनकी पार्टी कांग्रेस, जो संसद के दोनों सदनों की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसने वहां इन बातों को क्यों नहीं उठाया? क्या इसलिए कि उनकी पार्टी मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रही थी और सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रही थी?

जितना बड़ा खतरा चिदंबरम को इन विधेयकों के पास होने से दिख रहा है उतना ही बड़ा खतरा संसद में विधेयकों पर चर्चा नहीं होना या विपक्षी पार्टियों का उस चर्चा में हिस्सा नहीं लेना भी है। ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियां विधायी लड़ाई संसद के बाहर लड़ रही हैं। यह सही है कि सरकार के पास जिस तरह का बहुमत है उसे देखते हुए विपक्षी पार्टियां विधेयक को रोक नहीं सकती हैं। लेकिन संसद के अंदर अगर विपक्षी पार्टियां बहस में हिस्सा लेतीं तो वे विधेयकों की कमियां सामने लातीं। अपनी तरफ से संशोधन पेश करतीं, बेशक वह संशोधन नहीं मान्य होता। विधेयक की कमियों के बारे में लोगों को जागरूक करतीं। इसके खतरे बतातीं। लेकिन जब संसद में बिल पास हो रहे थे तब विपक्ष संसद परिसर में नारेबाजी कर रहा था और बिल पास हो जाने के बाद विपक्षी नेता

लेख लिख कर या ट्विट करके उसका विरोध कर रहे हैं।

पी चिदंबरम ने भी यही काम किया। उन्होंने बताया कि वन संरक्षण संशोधन कानून लागू होने से कितना नुकसान होना है। इस बिल में सहारे बड़े वन क्षेत्र को संरक्षित श्रेणी से हटाया जा रहा है। इसके कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और 2006 के वन अधिकार कानून के उलट हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक सौ किलोमीटर के अंदर जंगल की जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सोचें, यह कानून बनने के बाद समूचा पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र कितना प्रभावित होगा? इसका पूरा वन क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से सौ किलोमीटर के दायरे में ही आता है। विपक्ष चाहता था कि बिल पर संसद की स्थायी समिति में विचार हो लेकिन सरकार ने स्थायी समिति की बजाय इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा और वहां अपने बहुमत के दम पर इसे मंजूर करा लिया। प्रवर समिति के छह विपक्षी सांसदों ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बिल के कानून बनने से वन आच्छादित क्षेत्र में कमी आएगी, खास कर सीमावर्ती इलाकों में।

इसी तरह मल्टी स्टेट सहकारिता संशोधन कानून है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया एक प्राधिकरण सभी सहकारिता सोसायटीज के चुनाव कराएगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके सदस्यों की किसी भी शिकायत का निवारण केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त ओम्बुड्समैन करेगा। तीसरा कानून, जिसका जिक्र पी चिदंबरम ने किया वह दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा है। इसका नाम जीएनसीटीडी संशोधन कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने मई में एक फैसले के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया और अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए तीन सदस्यों का एक प्राधिकरण बना दिया। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और उनके अलावा दो वरिष्ठ अधिकारी उसके सदस्यों होंगे। फैसला बहुमत से होगा और अंतिम फैसला उप राज्यपाल करेंगे। आमतौर पर माना जा रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन कर परदे के पीछे से सरकार चलाने की केंद्र की योजना का यह भी एक पार्ट है।

दिलचस्प बात है कि आम आदमी पार्टी ने इस बिल को ऐसे पेश किया, जैसे यह इस देश के सामने मौजूद सबसे बड़ा संकट हो। उसके नेताओं ने खुलेआम कहा कि जो इस बिल का साथ दे रहा है वह देशद्रोही है और विपक्ष के नेता खुशी-खुशी इस नैरेटिव को बढ़ाने में उसके साथ शामिल हो गए। संसद के मानसून सत्र में यह एकमात्र बिल है, जिस पर दोनों सदनों में हुई चर्चा में विपक्ष के सांसद शामिल हुए। सोचें, अगर विपक्षी पार्टियां मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री का बयान मांगने के अपने अभियान को स्थगित करके या सीमित करके दिल्ली सरकार से जुड़े बिल पर बहस में हिस्सा ले सकती थीं तो उन्होंने बाकी जरूरी विधेयकों पर बहस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जीएनसीटीडी संशोधन बिल पर बहस से विपक्ष का व्रत नहीं टूटा और वन संरक्षण या मल्टी स्टेट सहकारिता या जन विश्वास या डाटा संरक्षण या माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बहस में हिस्सा लेने से व्रत टूट जाता?

जिस तरह से पी चिदंबरम ने बिल पास होने के बाद लेख लिख कर रूदन किया है उसी तरह कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विट करके जन विश्वास बिल की आलोचना की। ध्यान रहे यह बिल आम आदमी के लिए बेहद चिंताजनक है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी घटिया दवा से इलाज की वजह से मरीज की तबियत और खराब होती है या उसका निधन होता है तो दवा बनाने वाली कंपनी में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसे सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। यह बात सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विट में भी कही। तो सवाल है कि उनकी पार्टी ने यह बात संसद में क्यों नहीं उठाई? जिस समय बिल पास हो रहा था उस समय कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसद क्या कर रहे थे? किसी भी विपक्षी सांसद ने एक शब्द इस विधेयक के बारे में नहीं बोला है। इसी तरह डाटा संरक्षण बिल का मामला है। इसके प्रावधानों को लेकर अनेक सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। सूचना अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति की है लेकिन विपक्ष ने लोकसभा में इस पर बहस में हिस्सा नहीं लिया? यह बिल आम नागरिक के निजता के अधिकार को कमजोर करता है। यह बिल सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रचार इस बात का किया जा रहा है कि सरकार डाटा स्टोर करने वाली कंपनियों पर किसी गड़बड़ी में ढाई सौ करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है। इसका आम आदमी के लिए कोई मतलब नहीं है। उसके मतलब की बात यह है कि इस बिल में सरकार और सरकारी एजेंसियों को आम आदमी का डाटा हासिल करने और उसकी निगरानी करने के लिए कई तरह की छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि किन किन स्थितियों में सरकार और उसकी एजेंसियों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। पहले 2022 में जब यह बिल आया था तब संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर विचार किया था तब 90 से ज्यादा संशोधन सुझाए गए थे लेकिन सरकार ने संशोधित बिल लाने की बजाय बिल वापस ले लिया और 2023 में नया बिल पेश किया, जिसमें वो सारे प्रावधान रख लिए गए, जिनका संयुक्त संसदीय समिति में विरोध हुआ था। सो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार मनमाने तरीके से कानून बना रही है और शक्तियों का केंद्रीकरण कर रही है। लेकिन इस काम में कुछ हद तक विपक्ष भी शामिल है क्योंकि विपक्षी पार्टियां अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही हैं। वे राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाले मुद्दों को पकड़ कर संसद परिसर में प्रदर्शन करती रहती हैं ताकि अधिकतम मीडिया कवरेज मिले। जबकि उनकी विधायी जिम्मेदारी यह है कि वे सदन में बैठें और सरकार को विधेयकों के मामले में मनमानी करने से रोकें।

अजीत द्विवेदी

आम सी लड़की

सुन कर मोहब्बत के
अधूरे किस्से सहम जाती है
आम सी लड़की।
अजनबी लोगों को देख
घबराकर छुप जाती है
आम सी लड़की।
माँ के आंचल को,पापा के कंदे को
अपनी ढाल समझती हैं
आम सी लड़की।
इश्क़ तो दूर
उसके नाम से भी डर जाती है
आम सी लड़की।
इश्क़ लिखती है, इश्क़ पढ़ती है
मगर इश्क़ करने से डरती है
आम सी लड़की।
मिलती नहीं,दिखती नहीं
कहीं भी आजकल
आम सी लड़की।

राजीव डोगरा
जनयानकड़
कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश

आजादी का वंदन

गहन तिमिर में
हम साहस के,दीप जलाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।
चंद्रगुप्त की धरती है यह,
वीर शिवा की आन है।
राणाओं की शौर्य धरा यह,
पोरस का सम्मान है।
वतनपरस्ती तो गहना है,
हृदय सजाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।
शीश कटा,कुर्बानी देकर,
जिनने वतन सजाया।
अपने हाथों से अपना ही,
जिनने कफ़न सजाया।।
भारत माता की महिमा की,
बात सुनाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।
खून बहा,कुर्बानी देकर,
जिनने फर्ज़ निभाया।
वतनपरस्ती का तो जज़्बा,
जिनने भीतर पाया।।
हँस-हँसकर जो फाँसी झूले,
वे नित भाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।
सिसक रही थी माता जिस क्षण,
तब जो आगे आए।
राजगुरू,सुखदेव,भगतसिंह,बिस्मिल
वो कहलाए।।
ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने,
निज प्राण गँवाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।
आज़ादी पाई जो हमने,
उसको पोषित करना।
हर जन,नित सुख से रह पाए,
सबका दुख है हरना।।
हर भारत के वासी में हम,
देशभाव पाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।
संविधान है मान हमारा,
जन-जन का अरमान है।
भारत माँ का वंदन नित,
जन-गण-मन का गान है।।
आर्यवर्त की पुण्यभूमि को,
तीन रंग भाते हैं।
आज़ादी के मधुर तराने,
हम नित गाते हैं।।

प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे
मंडला,
मध्यप्रदेश

एक महत्वपूर्ण प्रश्न

वो हाथ बस यह आपके पास है
इसलिए क्या कर डाले
या आप क्या कर रहे हैं
आप जो कुछ भी कहते हैं
कुछ नहीं कर सकते...
कह नहीं सका
द रीज़न...आप अपने लिए हैं
आप के आसपास
उन लोगों के लिए जीकर जो हैं और
मतलबी होना इस राष्ट्र के लिए
आप कहते हैं कि आप सेवा करते हैं...
क्या ऐसा है? ठीक
एक महत्वपूर्ण प्रश्न
आप इस देश के हैं
क्या आप सेवा करते हैं?
या यह राष्ट्र आपको
बहुत सम्मान के साथ
क्या यह सेवा करता है?

ओटेरी सेल्वा कुमार,
चेन्नई,
तमिलनाडु

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

अनपेड इंटर्नशिप युवा पीढ़ी के लिए तनाव का कारण

आज हम जब आधुनिकरण की बात करते हैं तो ऐसे में पाते हैं कि इस समय बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। देश दुनिया की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई है। आज आधुनिक समय में लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है परंतु दूसरी ओर शिक्षा एक विकराल औद्योगिक रूप ले चुकी है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना हर आम आदमी के बस की बात नहीं। आज के समय में पढ़ाई से लेकर स्कूल कॉलेज एडमिशन को लेकर हर स्तर पर प्रतियोगिता एक दौड़ देखने को मिलती है। युवा जब ग्रेजुएट होकर कॉलेज से निकलते हैं तो उसके बाद नौकरी यह व्यवसाय की दौड़ शुरू हो जाती है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान या बाद में नौकरी शुरू करने से पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है। जिसका उद्देश्य तजुर्बा हासिल करना होता है। पर ऐसा देखने को मिलता है कि युवाओं में इंटर्नशिप को लेकर तनाव बना रहता है। बहुत सी कंपनियां तथा कार्यालय इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को कोई स्टाइपेंड नहीं देते हैं । जिसे अनपेड इंटर्नशिप कहा जाता है। इस तरह की इंटर्नशिप युवाओं को मजबूरी में करनी पड़ती है तथा यह उनके लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन जाती है। आज आधुनिक दौर में जब जिंदगी से जुड़ी हर चीज महंगी है । ऐसे में बिना स्टाइपेंड के अपना खर्चा निकालना मुमकिन नहीं । बल्कि उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च में पड़ते हैं । आज आधुनिक पीढ़ी कॉलेज खत्म होते ही अपने आप को आत्मनिर्भर पाना चाहती है । वह मां बाप या किसे से भी पैसे नही मांगना चाहते है । चाहे वह लड़का हो या लड़की । ऐसे में इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड का ना मिलना उन्हें हतोत्साहित करता है । जबकि युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है । सरकार द्वारा मजदूर एक्ट में बहुत सी बातों को कानून का आधार दिया गया है जिसके अंतर्गत चाइल्ड लेबर एक्ट भी आता है । जिसके अंतर्गत नाबालिक बच्चों से काम करवाना जुर्म है। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अन्य कई तरह के प्रोग्राम चलाई जा रहे हैं। परंतु इंटर्नशिप के दौरान दिए जाने वाले स्टाइपेंड को लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है । सवाल यह उठता है कि क्या यह शोषण नहीं है? क्या जो युवा अपना समय और एनर्जी किसी कार्यालय मे देता है उसे उसका उपयुक्त वेतन नहीं मिलना चाहिए? क्या इस विषय पर कानून बनाने के जरूरत नहीं ? लेबर एक्ट के तहत मजदूरों का मिनिमम देहाड़ी भी निर्धारित है । ऐसे मे अनपैड इंटर्नशिप क्या विचारणीय नहीं है? युवाओ को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने की ओर अनपेड इंटर्नशिप पर प्रतिबंध होना चाहिए। जिस से युवा पीढ़ी का प्रोत्साहन बड़े । आज के युवा ही देश का भविष्य है ।

केशी गुप्ता
द्वारका
दिल्ली

भारत की बढ़ती जनसंख्या में उप भोक्ताओं की पूंजी तलाशते पश्चिमी देश

सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ

भारत की वर्तमान में जनसंख्या भारी-भरकम देश चीन की जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई है। यानी कुल मिलाकर एक अरब चालीस करोड़ आबादी वाला भारत में जनसंख्या के बोझ तले विकास और उन्नति बेहद धीमी और अविकसित है। विकसित तथा समृद्ध देश भारत की जनसंख्या में एक संभावना वाला उपभोक्ता बाजार तलाशते हैं और इसे बहुत बड़ी पूंजी भी मानकर अपनी उपभोक्ता सामग्री भारत में बेचने का प्रयास करते हैं। केवल बाजार में निवेश और बाजारी ताकत ही विकास का पैमाना नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों को नष्ट कर देती है और विकास की धार को कमजोर करने का काम करती है। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो देश में बिजली, पानी की कमी बढ़ती महंगाई, फैलती विनाशकारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अशिक्षा के फैलाव पर नियंत्रण, गरीब व्यक्ति को और गरीब होने से रोकने का प्रभावी तरीका तथा सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाई जा सकती है। कम और नियंत्रित जनसंख्या तेजी से विकास का पैमाना हो सकती है। 1951 से लेकर 81 तक भारत में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इसे जनसंख्या विस्फोट का भी नाम दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने हेतु प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्तमान जनसंख्या का विशाल स्वरूप 1981 के बाद भारत में विशालतम हो गया है और आज की जो जनसंख्या का विस्फोट उसी की परिणति है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण अशिक्षा, अंधविश्वास और घटती मृत्यु दर भी है। सीमित संसाधन कमजोर आर्थिक व्यवस्था के कारण देश में बेरोजगारी भ्रष्टाचार गरीबी महंगाई पानी तथा बिजली की कमी बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम ही हैं। यह तो अत्यंत निश्चित है यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर ले तो हम अपने विकास की गति को दोगुना कर सकते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूपों को देखा जाए तो इसमें हम समावेशी विकास के रूप में देखकर आर्थिक विकास की उत्तर जनित राष्ट्रीय आय के विस्तृत

नियोजन में समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सही लाभ मिलने का नजरिया भी तलाशते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कर गरीबी को नीचे से ऊपर की ओर सुधारने का काम हमें करना होगा और इसके लिए यह जरूरी है की कमजोर और वंचित वर्गों जिनमें महिला, वृद्ध, एससी, एसटी,श्रमिक आदि शामिल हैं को समुचित लाभ मिलना चाहिए। बच्चे आने वाले देश के नागरिकों के लिए उचित एवं आवश्यक शिक्षा की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। वैसे जनसंख्या नियंत्रण ही विकास की समुचित धारा नहीं हो सकती हमें जनसंख्या के साथ सामाजिक आर्थिक सुरक्षा एवं सीमित संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर निरंतर आगे बढ़ना होगा लेकिन आवश्यकता संसाधनों के उचित दोहन नीतियों एवं कार्यक्रमों की है और आवश्यकता है नवाचार एवं उचित तकनीकी प्रौद्योगिकी की भी। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है उसके विपरीत चीन और जापान में निरंतर जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है इस तरह भारत में प्रचुर मानव संसाधन के स्रोत उपलब्ध हैं जिसका सही उपयोग करके भारत अपनी आर्थिक तथा सामरिक शक्ति को अत्यंत शक्तिशाली कर सकता है, इसके विपरीत भारत में विस्तृत रूप से गरीबी, बीमारियां, बेरोजगारी, जैसी विकराल समस्या में विद्यमान है। विश्व के कई कम आबादी वाले देश जैसे सोमालिया,लिथुआनिया आदि गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद की समस्या से दो-चार हो रहे हैं और कम जनसंख्या के बावजूद विकास नहीं कर पा रहे हैं ।जबकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देशों में चीन और अमेरिका विकसित राष्ट्रों की कतार में हैं एवं विकास के शीर्ष पर हैं। भारत के पास सभी संसाधन और विकसित होने के सारे अवयव हैं इसके बावजूद भारत विज्ञान, टेक्नोलॉजी में काफी पीछे होकर अशिक्षा, अंधविश्वास ,कृषि कार्यों का निम्न स्तर आर्थिक असमानता की समस्याएं झेल रहा है जो भारत के विकास में बाधक है। भारत में अब आज की व्यवस्था में जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए इसके साथ जरूरत है जानते हैं कि समस्याओं को उत्पन्न करने में हम ही लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं हम लोग को यह समझना होगा कि समस्याओं से निपटने की हमारी भूमिका उतनी ही अहम है जितनी शासन-प्रशासन की। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण उपलब्ध संसाधनों के समुचित सही दोहन की जिम्मेदारी हम सब पर होती है इसमें समुचित सहयोग प्रदान करना होगा तब जाकर भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा हो सकता है।

संजीव ठाकुर,
चौबे कालोनी रायपुर छत्तीसगढ़

महिलाओं में अनियमित माहवारी से मंडराया डायबिटीज का खतरा

भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। दुनियाभर में मधुमेह के जो मरीज हैं, उसमें से 17 त्न अकेले भारत में हैं। यूनाइटेड किंगडम के जनरल लैंसेट में प्रकाशित आईसीएमआर के अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत में 70 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रसित थे। माना जा रहा है कि जल्द ही ये आंकड़ा बढ़कर 101 मिलियन हो जाएगा। अध्ययन में आगे कहा गया कि मधुमेह के प्रसार की दर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कहीं ज्यादा है। जहां पुरुषों में यह 8.5प्रतिशत है, वहीं महिलाओं में इसकी दर 10.2 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आशंका है कि महिलाओं में तेजी से बढ़ता मधुमेह उनमें माहवारी की अनियमितता, उम्र से पहले मोनोपॉज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जोखिम को बढ़ा सकती है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि महिलाओं में बढ़ती मासिक अनियमितता और पीसीओएस उनमें मधुमेह का जोखिम भी उत्तपन्न कर सकता है।

2013 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि माहवारी के ल्यूटल फेज के दौरान महिलायों के रक्त में शर्करा का स्तर ज्यादा था। दरअसल मासिक चक्र के ल्यूटल फेज में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाता है,जिससे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और प्रीडायबिटीज की स्थिति बनाता है। अगर माहवारी लंबी चले या अनियमित हो तो बढ़े हुए प्रोजेस्ट्रान का लेवल कोशिकाओं को इंसुलिन प्रतिरोधी बनाता है। नतीजा महिलाएं टाइप-2 डायबिटीज की शिकार हो जाती हैं। ऐसे हालात में डॉक्टर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बार-बार मधुमेह की जांच कराने की सलाह देते हैं। माहवारी नियमित रहे इसलिए पोषणयुक्त आहार लेने को कहते हैं।

2020 में प्रकाशित अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक जनरल में इस बात का खुलासा हुआ कि , मासिक धर्म और मधुमेह में घनिष्ठ संबंध है। जनरल में बताया गया कि वे महिलाएं जो मोटापे की शिकार है एवं जिनमें महावारी अनियमित है वे मधुमेह के हाईरिस्क जोन में हैं।

आंकड़ों की मानें तो आज भारत में 5 में से एक महिला पीसीओएस से पीड़ित है। महिला मधुमेह रोगियों की बढ़ती संख्या इसमें इजाफा कर सकती हे। टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित महिला का अग्नाशय अधिक मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है। यह ओवरीज में एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। नतीजतन ओवरीज को ओव्यूलेट करने में समस्या आती है और माहवारी समय पर नहीं आती और ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कम कार्बोहाइड्रेट और शर्करा वाला भोजन करने की सलाह देते हैं ताकि इंसुलिन के लेवल को बैलेंस किया जा सके।

आईसीएमआर के ताजा आंकड़ो के अनुसार भारत में 136 मिलियन लोग 15.3त्न प्रीडायबिटीज के हैं। इस अध्ययन के अनुसार 4 सालों में भारत में मधुमेह के 44 प्रतिशत मामले बढ़े हैं। जो कि 2019 में 70 मिलियन थे।

शोधशास्त्रियों को आशंका है कि आने वाले 5 सालों में प्रीडायबिटिक के आधे मरीज टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे। जहां एक ओर तेजी से बढ़ते मधुमेह के मरीज चिंता का विषय हैं, वहीं दूसरी ओर नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मॉनिटरिंग सर्वे की मानें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मधुमेह का प्रसार तीव्र है।यदि यह स्थिति बनी तो भविष्य में महिला मधुमेह मरीज़ों की संख्या बढ़ेगी जो निश्चित तौर पर महिलायों में माहवारी अनिमियता और पीसीओएस का संकट बढ़ाएगा ।

सीमा अग्रवाल,
मेरठ,
उत्तरप्रदेश

श्री डी. के सोनी

छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष - हिल द वर्ल्ड फाउंडेशन, दिल्ली
छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष - राष्ट्रीय मानव अधिकार संसाधन विकास संस्था, नागपुर
छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष - अखिल भारतीय स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन
अध्यक्ष - सरगुजा सोसाइटी फॉर जस्टिस, अम्बिकापुर
सदस्य - नेशनल फेडरेशन ऑफ़ सोसाइटी फॉर फ़ास्ट जस्टिस, दिल्ली
सदस्य - सरगुजा स्वर्णकार समाज

पारिवारिक जानकारी

पिता: **स्व. रामजी प्रसाद सोनी**
माता: **श्रीमती किरोधा देवी**
पत्नी: **श्रीमती रजनी सोनी**
जन्मदिन: **12 अगस्त 1976**
शिक्षा: **बीए, एलएलबी**
कार्यक्षेत्र: **सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ वकालत, सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता।**
पुत्र: **स्पर्श सर्राफ**
इंटरनेशनल स्पीड बॉल खिलाड़ी हैं जो कई मेडल जीतकर सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किये हैं।
पुत्र: **शौर्य सर्राफ**
फेंसिग (तलवारबाजी) का नेशनल खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा भी कई मेडल जीतकर सरगुजा का नाम रोशन किया गया है।
शौर्य सर्राफ का जन्मदिन 13 अगस्त को है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक पहचान

एक शख्स जिसने भ्रष्टाचार को रोकने आवाज़ उठाई, एक शख्स जिसने गांव की गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों और न्यायालय तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कोई इन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जानता है तो कोई इन्हें समाजसेवी कहता है। कई नामों से जाने जानेवाले इस शख्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी है कि लाखों रुपये का अर्थदंड भ्रष्टाचारियों को भरना पड़ा है। लोगों को मनरेगा की लंबित मजदूरी से लेकर ठेकेदारों द्वारा रोके गये रकम तक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनरेगा योजना में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी अधिकारियों से इन्होंने कराई है। इस नेक कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। इस शख्स ने अपनी एक अलग पहचान प्रदेश में कायम की है। पेशे से अधिवक्ता और अम्बिकापुर निवासी दिनेश सोनी अर्थात डी के सोनी से कौन वाकिफ नहीं है। जिनके नाम से ही भ्रष्टाचारियों कि नींद हराम हो जाती है।

डीके सोनी जो की छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले सरगुजा के अंबिकापुर में रहते हैं और वकालत के साथ-साथ आरटीआई कानून के माध्यम से आदिवासियों के हित के मुद्दो को हमेशा उठाया है, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेता के विरुद्ध कई मामलों में कार्यवाही कराते देखे गए हैं। मनरेगा योजना में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी अधिकारियों से इन्होंने कराई है। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं सहित अन्य योजनाओं व भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस के आलावा ग्राम न्यायालय की स्थापना कराने और घर पर न्याय की परिकल्पना को पूरा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई है, इसके अलावा सरगुजा के घने जंगलों जिसमे हसदेव अरण्य आता है उसे कोल उत्खनन के लिए काटने की अनुमति दे दी गई जिसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के खिलाफ भी जनहित याचिका लगाया है। जल, जंगल और आदिवासियों की जमीन को बचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह समय समय पर और भी जनहित के कार्यो में खेल संघों को आगे बढ़ाने में इनकी विशेष रुचि है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर वनांचल क्षेत्र अंबिकापुर से आने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट डी.के सोनी जी जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं उनके द्वारा हमेशा से भ्रष्टाचार, न्याय में देरी एवं विभिन्न क्षेत्र में समाज सेवा हेतु अनेक उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं जिसके लिए उन्हें समय-समय पर सम्मानित भी किया गया है।

श्री डी.के सोनी आम जन के लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम और शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु अपनी संस्था सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के माध्यम से हमेशा जमीनी एवं कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन के लिए भी एक लंबी लड़ाई जारी रखी हुई है।

श्री डी. के सोनी कई पुरूस्कार व अवार्ड से नवाज़े जा चुके हैं

सरगुजा संभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य में गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप उन्हें वर्ष 2017 में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस संस्था मुम्बई के द्वारा हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में विधि मंत्री एवं जस्टिस के हाथों ओपी मोगा नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संसाधन विकास संस्था के द्वारा 14/01/2021 को पूर्व राज्यमंत्री उत्तरप्रदेश श्री भत्ते चंदिया के द्वारा वाराणसी के सारनाथ में छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार के संबंध में तथा आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों में उत्कृष्ट कार्य करने के हेतु राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया।

ग्लोबल स्कोलर फाउंडेशन के द्वारा 28/08/2022 को भारतीय रत्न अवार्ड के तहत पूणे महाराष्ट्र में डॉ.जी पद्माजी रेड्डी के द्वारा विधिरत्न से बेस्ट एडवोकेट का एवार्ड प्रदान किया गया।

डब्ल्यू वी आर कॉर्प के द्वारा आइकोनिक अचेवर्ड के तहत 15/10/2022 को मुम्बई के होटल हॉलिडे ईन में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर श्री संदीप पाटिल एवं फिल्म एवं टीवी एक्टर श्री शक्ति अरोरा के हाथो बेस्ट सामाजिक कार्यकर्ता का अवार्ड प्रदान किया गया।

नेशनल हयूमन राईटस ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशन एचिवर्ड के माध्यम से 21/11/2022 को अमृतसर के होटल रेडिशन ब्लू में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी तथा केनिया देश के अम्बेस्टर श्री पेट्रिक के हाथों बेस्ट सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता का इन्टरनेशन एचिवर्ड अवार्ड दिया गया।

नेशनल एन्टी हरेशमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 11/12/2022 को भोपाल में मेजर जनरल तेजपाल सिंह रावत एवं फिल्म एक्टर अरुण बक्शी के हाथों बेस्ट आरटीआई कार्यकर्ता का भारतभूषण सम्मान अवार्ड दिया गया।

इंटरनेशन ह्यूमन राईट एवं क्राईम कन्ट्रोल काउसिंल तथा नेशनल एन्ट्री करप्शन के द्वारा 21 जनवरी 2023 को अद्भुत भारत सम्पन्न भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत गोवा के पार्क रेगिस होटल में मलेशिया देश की प्रतिनिधि स्वाति एवं इन्टरनेशन ह्यूमन राईट एवं क्राईम कन्ट्रोल काउसिंल के आकाक्षा विद्यार्थी के हाथो पृथ्वी रत्न अवार्ड प्रदान किया गया।

हयूमन प्राइड ग्रुप के द्वारा कॉन्स्टिटयूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में 13 फरवरी 2023 को बेस्ट आरटीआई कार्यकर्ता का अवार्ड मिस इंडिया 2013 सिमरन अहूजा, बिग बी जुनियर अरूण अरोडा तथा भारतीय नमो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों प्रदान किया गया।

डब्ल्यूबीआर कॉर्प संस्था के द्वारा 17/2/2023 को दिल्ली के रेडिशन ब्लू हॉटल में दृश्यम 2 की एक्ट्रेस इंशिता दत्ता के हाथो मोस्ट प्रॉमिसिंग कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया।

वर्ल्ड चेरिटेबल फाउडेशन संस्था के द्वारा 30/6/2023 को विशाखापट्टनम के पब्लिक लाइब्रेरी हॉल में आंध्रप्रदेश की एक्ट्रेस संध्या रानी नायक और शिल्पा नायक के हाथों बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड प्रदान किया गया।

ग्लोबल चेंबर ऑफ कंज्यूमर राइटस एवं किक्राफ्ट प्रोडक्शन के द्वारा 15/7/2023 को हॉटल विवान्ता इन ताज द्वारिका में पाण्डुचेरी की पूर्व राज्यपाल एवं देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के हाथो इंडिया आइकोनिक बेस्ट सोशल जस्टिस 2023 अवार्ड प्रदान किया गया।

इसी माह पिछले दिनों 6 अगस्त 2023 को ग्रो भारत फाउन्डेशन के द्वारा भारत श्री राष्ट्रीय सम्मान 2023 का बेस्ट आरटीआई कार्यकर्ता का अवार्ड फिल्म एक्टर गुस्ताख खान, ले.जनरल बी.एस सिसोदिया इंडियन आर्मी एवं एयर मार्शल श्री शशि खेर चौधरी के हाथों मध्य प्रदेश इन्दौर के वॉव हॉटल में प्रदान किया गया।

स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष
सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट, समाजसेवी एवं अधिवक्ता

12 अगस्त

श्री डी.के. सोनी जी

को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनायें

विनीत : समस्त मित्रगण एवं शुभेच्छु, जिला - सरगुजा

फर्जी पट्टा वितरण,पेयजल की समस्या को लेकर सामान्य सभा में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

नगर निगम की सामान्य सभा शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से सरगुजा सदन में सभापति अजय अग्रवाल की उपस्थिति में शुरू की गई। सबसे पहले नवपदस्थ निगम आयुक्त का स्वागत किया गया। बैठक की शुरूआत हंगामेदार रही। निगम क्षेत्र में पेयजल की ज्वलंत व गंभीर समस्या को सत्तापक्ष द्वारा एजेंडे में 20 नंबर पर रखे जाने पर विपक्ष ने आपति जताते हुए कहा कि पेयजल शहर का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और उसे एजेंडे में अंतिम में रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज ने कहा कि 106 करोड़ की राशि का दुरुपयोग किया गया है। अगर इस राशि का सही से उपयोग किया गया होता तो आज शहरवासियों को पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। विपक्ष ने कहा कि अगर अमृत मिशन के तहत पैसा नहीं आता तो कई लोग पेयजल की समस्या से ग्रसित होकर शहर छोड़ पलायन कर जाते। इतनी बड़ी गंभीर समस्या को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा एक बार भी चर्चा नहीं की गई। अभी भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। बांकी डेम में मात्र दस प्रतिशत ही पानी भर पाया है। अगर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो आने वाले कुछ दिनों में पुनः स्थिति खराब हो सकती है। वहीं मामले में सत्ता पक्ष से पीडब्ल्यूडी प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि अब धीरे-धीरे पेयजल की समस्या में सुधार हो गया है। इस गंभीर समस्या के प्रति विपक्ष को खुद भी आगे आकर चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद भाजपा समर्थित पार्षद आलोक दुबे ने शासन के नियम के तहत नजूल भूमि पर 152 प्रतिशत के तहत पट्टा देने के मामले में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। आलोक दुबे ने कहा कि मात्र 20 प्रतिशत पट्टा शासन के नियम के तहत दिया गया है। बाकी 80 प्रतिशत पट्टों में बिना जांच के नगर निगम द्वारा एनओसी दे दिए गए हैं। पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो नगर निगम को जरूरत पडने पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। शासन के नियम के तहत वर्ष 2017 के पहले से भूमि पर काबिज हितग्राही को 7 डिसिमल के अंदर के लिए एनओसी देना है। लोग रह कहीं और रहे हैं और उन्हें पट्टा के लिए एनओसी कहीं और का दे दिया गया है। सहायक नजूल अधिकारी द्वारा 1578 लोगों को एनओसी दे दिया गया है, जबकि यह मात्र 20 प्रतिशत ही सही है। 80 प्रतिशत एनओसी गलत तरीके से दे दिया गया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की ओर से शफी अहमद ने कहा कि शासन के पत्र के अनुसार 152 प्रतिशत के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में निगम आयुक्त भी रहते हैं। विपक्ष द्वारा फर्जी तरीके से एनओसी देने का आरोप लगाया गया है तो इसकी जांच कराई जाएगी। गूगल मैप से जांच कराई जाएगी कि वास्तविक कब्जे की स्थिति क्या है। विपक्ष के पार्षद मधुसूदन शुक्ला ने आरोप लगाया कि सडक़ों का डामरीकरण आधा-अधूरा कराया गया है। निविदा पूरी सडक़ की होती है और डामरीकरण आधी सडक़ का कराया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में डामरीकरण का काम बंद करा दिया गया और आनन फानन में बारिश के दिनों में कुछ विशेष सडक़ों पर डामरीकरण कराया जा रहा है। जबकि सडक़ें सभी बननी चाहिए पर सडक़ डामरीकरण में भेदभाव किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष की ओर से शफी अहमद ने कहा कि 22 करोड़ की राशि स्वीकृत है। ठेकेदार द्वारा काम कराया जा रहा है। रिटेंडर भी कराया गया है। 15 सितंबर के बाद पुनः सडक़ों का डामरीकरण का कार्य शुरू कराया जाएगा। समय सीमा के तहत कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

विपक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाया कि नालियों पर किए गए अतिक्रमण के कारण बारिश में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश में नव निर्मित नाला पानी में बह गया, गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शासन की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर शफी अहमद ने निर्माण प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि देवी गंज रोड में 15 दिन के अंदर नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करें। वहीं बारिश में नाला बह जाने के मामले में शफी अहमद ने कहा कि मैंने पूर्व में ही इस मामले में निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग संवर्ग एवं चिकित्सकों ने आंदोलन किया शुरू

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग एवं चिकित्सकों द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को नर्सिंग संवर्ग एवं चिकित्सक एकजुट होकर अस्पताल के प्रवेश द्वार में जमकर नारेबाजी की और लंबे समय से की जा रही मांगों के परिप्रेक्ष्य में सरकार को आइना दिखाया। उपमुख्यमंत्री व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह जिले व नगर में शुरू किए गए आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि उनकी मांगों को शासन-प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है। हाल में अनुपूरक बजट में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपेक्षा की गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन अपनी मांगो को लेकर प्रांतव्यापी चरणबद्ध आंदोलन 11 अगस्त से शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य अमले के महत्वपूर्ण घटकों का दावा है कि उनकी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 21 अगस्त से उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रस्तावित है। इनकी मांगों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के एएनएम, एमपीडब्ल्यू एवं स्टाफ नर्स की वेतन विसंगति विभाग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान अनुरूप दूर करना एवं चिकित्सकों के वेतनमान, वेतन, स्टाइपेंड संबंधी मांग को जल्द पूरा करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कोरोना काल में सेवा देने वाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कोरोना भत्ता का भुगतान करना सहित अन्य मांगें शामिल है।

परिवीक्षा अवधि के नर्सिंग स्टॉफ ने संभाला अस्पताल

अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या ने बताया कि जिला अस्पताल की नर्सों व मेडिकल स्टॉफ की हड़ताल को देखते हुए 160 परिवीक्षा अवधि के नर्सिंग स्टॉफ को अस्पताल की जि मेदारी सौंपी गई है। एकस-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन जांच में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हुआ है। अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं पूर्ववत मिल रही हैं। ओपीडी व आईपीडी में भी स्थिति सामान्य बनी हुई है।

अजब-गजब राजनीति की वजह से बची नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी

-संवाददाता-
कुसमी,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

नगर पंचायत कुसमी में पिछले कई दिनो से नगर पंचायत के अध्यक्ष गोवर्धन भगत पर पक्ष विपक्ष दोनो पार्षदो नें मिलकर अविस्वास प्रस्ताव लगाया था,दरसल पक्ष कांग्रेस विपक्ष भाजपा दोनो के पार्षद नें अध्यक्ष के उपर ट्रेक्टर खरीदी में भष्टाचार पार्षदो का अनदेखी करने का आरोप लगाते हुये नाराज पार्षद गणो ने अविस्वास लगाया जिसका वोटिंग शुक्रवार के दिन हुया जिसपर अध्यक्ष को कुर्सी बचाने के लिये 6 वोट की आवश्यकता थी जो पार्षदो की वोटिंग से वो मिल गया और अध्यक्ष खिलाफ 9 वोट पडे, जीत के बाद कांग्रेसियो नें पटाखे फोडकर जीत का जश्न मनाया और संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक चिन्तामणी महाराज के साथ मिलकर कांग्रेसीयो नें शहर मे रैली भी निकाली, बहरहाल भाजपा कांग्रेस के पार्षद गण जैसा एकजुटता दिखा रहे थे की लोगो को लग रहा था की अध्यक्ष की कुर्सी नही बचेगी लेकिन कांग्रेस नें अजब गजब की राजनीति दिखाई और अपने नाराज पार्षदो को समय रहते मना लिया जिससे अध्यक्ष की कुर्सी गिरने बच गई,

मेरी माटी-मेरा देश के तहत किया गया पौधा रोपण

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, अम्बिकापुर में 11 अगस्त को महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एसके सिन्हा के मार्गदर्शन में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत एनएसएस स्वयं सेवकों, ग्रामीणों एवं महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पौध रोपण का कार्यक्रम सूरजपुर जिले के ग्राम संबलपुर में किया गया। इसके पश्चात् महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा एनएसएस स्वयं सेवकों को पौध रोपण की महत्ता बताया गया एवं जीवन में अनुशासन को किस तरह से बनाया रखा जाय उस विषय पर भी चर्चा की गई। इसके पश्चात् ग्राम-संबलपुर, सरपंच क्रांति सिंह द्वारा भी एनएसएस स्वयं सेवकों द्वारा किए गए पौध रोपण की सराहना की गई। इस कार्यक्रम में कमल बिहारी, अनिल कुजूर एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. व्हीके सिंह, डॉ. जीपी पैंकरा, सहप्राध्यापक डॉ. नीलम चौकसे, सहायक प्राध्यापक डॉ. एसआर दुबोलिया ग्रामीण एवं एनएसएस के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

मंदिर के सिढ़ी से गिरे जख्मी व्यक्ति की मौत

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

मंदिर की सिढ़ी से गिरकर एक व्यकित गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार श्यामलाल पिता मोहर साय पनिका उम्र 60 वर्ष कोरिया जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र के छेटी बाजार का रहने वाला था। वह 10 अगस्त का काली मदिर हल्दीबाड़ी दर्शन करने गया था। इस दौरान वह मंदिर की सिढ़ी से गिर गया था। परिजन उसे इलाज के लिए चिरमिरी अस्पताल में भर्ती कराए थे। यहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

भैंस के हमले में जख्मी बालक की मौत

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

8 वर्षीय बालक पर भैंस ने हमला कर दिया। इससे बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राहुल राजवाड़े पिता दादी राम उम्र 8 वर्ष सूरजपुर जिले के बसदेई का रहने वाला था। वह बुधवार को घर के बाहर खड़ा था। तभी घर का भैंस उसपर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए सूरजपुर अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहा इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

14 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ का अयोजन

-संवाददाता-
सूरजपुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशन तथा कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम के सफल मार्गदर्शन में 14 अगस्त 2023 को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में किया जाना है। खेल अधिकारी श्रीमती आरती पाण्डेय ने बताया कि स्वतंत्रता दौड का आयोजन 14 अगस्त को प्रातः 7:00 बजे पुराना रेस्ट हाउस, जिला कोर्ट के सामने से प्रारंभ होकर अग्रसेन चौक होते हुये स्टेडियम ग्राउण्ड में संपन्न होगी। स्वतंत्रता दौड में जिले के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, मीडिया, खिलाड़ी सहित महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र-छात्रा भाग लेंगे।

एसिड अटैक के संबंध में आयोजित विधिक शिविर

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव अमित जिंदल के मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की श्रद्व1 कुमारी दुर्गा सिंह के द्वारा आज दिनांक 6/08/23 को अम्बिकापुर के अजीरमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर वहां उपस्थित छात्रों को एसिड हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एसिड अटैक अपराध का एक ऐसा खतरनाक रूप है जो पीड़ित का

जीवन दयनीय बना देता है। यह मूल रूप से किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। एसिड अटैक (तेजाब फेंकना) की शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं। इसके पीछे एक सामान्य कारण है प्रेम संबंधी विवाद है यह समस्या छोटी सोच वाले लोगों के कारण उत्पन्न होती है जो अपने जीवन में अस्वीकृति का सामना नहीं कर सकते। एसिड हमले का नुकसान ये होता है की तेजाब के कारण पीड़ितों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है, साथ ही चेहरे और शरीर पर स्थायी निशान पड़ जाते हैं, खोपड़ी आंशिक रूप से नष्ट हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं, कान आमतौर पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है बहरापन हो सकता है, नाक सिकुड़ सकती है पूरी तरह से बंद हो सकती है कभी-कभी होंठ और गाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं और द खाना और बोलना मुश्किल हो जाता है। तेजाब हमले की पीड़िताओं की कभी कभी मौत भी हो जाती है। देश में एसिड अटैक जैसे खतरनाक और जानलेवा - अपराध को रोकने के लिए कड़े क़ानून बनाये गए हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 326, के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अगर जानबूझकर अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका और स्थाई या आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया तो इसे गंभीर जुर्म माना जाएगा। अपराध गैर मानती होगा। दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। यह भी प्रावधान है कि दोषी पर उचित जुर्माना होगा और यह रकम पीड़िता को दिया जाएगा।

अधिवक्ताओं को कभी भी अप्रिय स्थिति का करना पड़ता है सामना, इस लिए सुरक्षा कानून जरूरी

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के आह्वान पर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाये जाने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय प्रांगण जिला अधिवक्ता संघ द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन का किया गया। जिसमें प्रमुख तौर पर राज्य सरकार द्वारा जिला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का कानून बनाए जाने एवं अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा कराए जाने तथा अधिवक्ताओं की मृत्यु की स्थिति में दस लाख रुपये का मृत्यु दावा दिलाए जाने की मांगों को लेकर किया गया। उपरोक्त मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। उपरोक्त आंदोलन अध्यक्ष हेमंत तिवारी के नेतृत्व में किया गया तथा मंच का संचालन सचिव विजय तिवारी द्वारा किया गया। धरना में वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्तागण केएन तिवारी, जेपी श्रीवास्तव, अशोक दुबे, राजेश तिवारी, गिरवर प्रजापति, दिलीप विश्वास, जनार्दन त्रिपाठी द्वारा विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि वास्तव में जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व अधिवक्ता ही करता है तथा जनता जब समस्याओं में घिरी रहती है, तो अधिवक्ता ही राजस्व अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के समक्ष उसका बचाव तथा संरक्षण करता है। जिसमें अधिवक्ता को अधिकारियों के समक्ष कभी-कभी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है तथा अधिवक्ताओं के विरुद्ध दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर अपराध तक पंजीकृत किए जा रहे हैं तथा राजस्व जैसे न्यायालयों में अधिवक्ताओं को कभी-कभी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं गरीब, पीड़ित लोगों का पैरवी, भू-माफियाओं, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगों तथा अधिकारियों के विरुद्ध करना पड़ता है, जिसके कारण ऐसे लोगों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता है, उस स्थिति में अधिवक्ताओं को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है, जिस कारण से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना अति आवश्यक है। धरना प्रदर्शन में अधिवक्तागण केएन तिवारी, केएन पाण्डेय, अशोक सिंह, अशोक दुबे, प्रमोद तिवारी, अरविन्द सिंह, राजीव सिन्हा, राजेश सिन्हा, उमंग दुबे, राकेश सिन्हा, शत्रुधन सिंह, अनुप टेकाम, मनोज तिवारी, मनोज अम्बष्ट, प्रवीण गुप्ता, श्याम नारायण पाण्डेय, ज्योति सिंह, प्रीति सोनी, आशा तिवारी, अनिमेष तिवारी, मोन्टी गुप्ता, अनिल सिंह आदि लोग प्रमुख तौर पर नी उपस्थित थे।

संघर्ष समिति बनाकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी

विदित हो कि, राजनैतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने हेतु घोषणा की गई थी, डॉक्टरों का सुरक्षा कानून बन गया, पत्रकारों का सुरक्षा कानून बन गया, परंतु आज तक अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु कानून नहीं बन पाया है। धरना के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि, शुक्रवार को सांकेतिक आंदोलन है तथा सरकार से निवेदन किया जा रहा है, यदि मांगों को नहीं मानी गई तो भविष्य में संघर्ष समिति बनाकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जायेगा।

अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक को उप जिला निर्वाचन अधिकारी का मिला प्रभार

-संवाददाता-
अंबिकापुर,11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर संयुक्त कलेक्टर श्री सुनील कुमार नायक, जिला राजनांदगांव को अपर कलेक्टर जिला सरगुजा के पद पर पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा श्री सुनील नायक अपर कलेक्टर जिला सरगुजा का कार्यभार ग्रहण किए जाने के फलस्वरूप अगामी आदेश पर्यन्त उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सरगुजा का प्रभार सौंपा गया है।

क्या पटना थाने के सामने पैसे का लेनदेन करने वाले प्रधान आरक्षक की जांच के लिए थाने के सीसीटीवी की हो गई जांच?

प्रधान आरक्षक की खुल सकती है पोल इसलिए नव पदस्थ पटना प्रभारी को अपनी गिरफ्त में करने की जुगत में लगे प्रधान आरक्षक

- कोई है जो सुपर कॉप प्रधान आरक्षक के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करेगा?
- पटना थाना के नए प्रभारी स्वयं आकर नहीं कर सकते थे पदभार ग्रहण, जो प्रधान आरक्षक को लेकर आना पड़ा?
- गांजा व सट्टा प्रकरण में पैसे के लेनदेन को लेकर प्रधान आरक्षक की भूमिका संदिग्ध, दोनों मामले पटना थाने में दर्ज
- आखिर क्या वजह है की सुपर कॉप प्रधान आरक्षक की शिकायतों पर उच्च अधिकारी हो जाते हैं मौन,कहीं अधिकारियों को वश में करने में माहिर तो नहीं प्रधान आरक्षक?

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,11 अगस्त 2023 (घटती-घटना)। जब भी कोरिया जिले में खराब पुलिसिंग की बात सामने आती है तो एक प्रधान आरक्षक का नाम उसमे जरूर शामिल रहता है, यह प्रधान आरक्षक कितने चर्चित है और कितने जुगाड़ू हैं इन्हें सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता है, लाख शिकायत और गलतियों के बाद अधिकारियों की मेहरबानी इन पर बरसती रहती है, जिसका नतीजा यह है की किसी भी कार्यवाही से बार-बार बच निकलते हैं, इन पर कार्यवाही करने के लिए ईमानदार छवि वाले अधिकारी को कोरिया जिले की कमान देनी होगी, अब वह अधिकारी कब आएंगे यह तो समय की बात है, अनगिनत शिकायतें और कई बार हुई फजियतों के बावजूद प्रधान आरक्षक की कार्यप्रणाली में सुधार आने की संभावना दिखती नहीं है, समय दर समय इनके ऊपर आरोप ना लगे यह तो मुमकिन नहीं, पूर्व शिकायतों को छोड़ दिया जाए और वर्तमान की बात की जाए तो इनके ऊपर थाने के सामने पैसा लेनदेन की बात का भी आरोप लगा है, भले ही शिकायत नहीं हुई पर यह बात पूरी तरह से सर्वजनिक हो चुकी है, जिसका साबुत थाने के ही सीसीटीवी में कैद है, ऐसा दावा है वहीं उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी भी है लेकिन इसके बावजूद उस सीसीटीवी की ना तो जांच हो रही है और ना ही प्रधान आरक्षक पर कोई कार्यवाही हो रही है और ना ही इस पर कोई कार्यवाही होनी है, यह भी सभी को पता है क्योंकि प्रधान आरक्षक अधिकारियों को किस कदर गिरफ्त में ले चुके हैं यह किसी से छुपा नहीं है, सट्टा प्रकरण में भी पैसे के लेनदेन को लेकर इनका नाम खूब चर्चा में रहा, जिस वजह से कई लोग बच निकले थे और जो पकड़े थे उनसे जमकर उगाही हुई थी, जिसे लेकर चर्चा आम हुई थी, प्रधान आरक्षक जितने मामले सुलझा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा तो उलझा कर पुलिस विभाग को ही बदनाम कर देते हैं, यही वजह है कि इनके साथ कोई काम करने को नहीं तैयार होता, जहां यह होते हैं वहां से कर्मचारी 100 कोस दूर भागना चाहते हैं कि यह काम तो खुद करेंगे और दूसरे को फंसा कर निकल जाएंगे। पर उच्च अधिकारियों को प्रधान आरक्षक कुछ ऐसे अपने गिरफ्त में कर रखे हैं कि उनसे अच्छा पुलिस वाला कोई है ही नहीं जो बड़े से बड़े मामला सुलझा सकता है, पर कई ऐसे बड़े मामले हैं जो आज तक अनसुलझे हैं जिसमें से तत्कालीन मामले पर ही गौर किया जाए तो पांडवपारा का चोरी मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया, यहां तक कहे तो पुलिस उसको सुलझा पाने में असमर्थ है, जबकि उस मामले में भी सुपर कॉप प्रधान आरक्षक आगे होकर चल रहे थे। एक चोरी के मामले में तो प्रधान आरक्षक के कहने पर प्रभारी साहब ने एफआईआर

दर्ज नहीं की यही वजह है कि पटना थाना से महज 300 मीटर दूर चोरी की घटना वाले मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अब नए पुलिस थाना प्रभारी पदस्थ हुए हैं अब देखना है कि मामला पंजीबद्ध होता है या नहीं? और इस बार नव पदस्थ थाना प्रभारी प्रधान आरक्षक की गिरफ्त से बाहर रहेंगे या फिर उसी से सहायता प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे यह देखने वाली बात होगी।

पटना थाना प्रभारी के सहयोग से प्रधान आरक्षक अपने दो आरोपों को निपटा सकते हैं

पटना थाना प्रभारी जो अभी हाल ही में पटना थाना प्रभारी के तबदला होने के बाद कार्यभार ग्रहण किए हैं और जिनको कार्यभार ग्रहण कराने खुद प्रधान आरक्षक पहुंचे थे, सूत्रों की माने तो प्रधान आरक्षक पटना थाने में ही लगे अपने दो आरोपों को निपटा सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। एक मामला पुलिस थाना पटना के सामने पैसे लेनदेन का है और जैसा कि दावा है की उक्त लेनदेन पुलिस थाना पटना के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है को प्रधान आरक्षक जरूर सीसीटीवी से मिटवाने का प्रयास करेंगे और वह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट करा कर ही दम लेंगे यह माना जा रहा है, इसलिए वह नव पदस्थ थाना प्रभारी के साथ उनका कार्यभार ग्रहण कराने भी पहुंचे थे जिससे पटना थाने का उनके खिलाफ का मामला वह थाना प्रभारी से निपटावा सकें। अब थाना प्रभारी प्रधान आरक्षक के मामले को निपटाते हैं यह निष्पक्ष होकर मामले में प्रधान आरक्षक के विरुद्ध जांच करते हैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखते हैं यह देखने वाली बात होगी।

पटना थाना की सीसीटीवी के फुटेज को रखना होगा सुरक्षित पर क्या रख पाएगी पुलिस उसे सुरक्षित?

पटना थाने की सीसीटीवी फुटेज में प्रधान आरक्षक की पैसे की लेनदेन जो थाने के समाने हुई है वह दर्ज हुई है। प्रधान आरक्षक का लेनदेन सीसीटीवी में दर्ज हुआ है यह दावा पूरे विश्वास के साथ किया जाने वाला दावा है, अब देखना यह है की क्या उस सीसीटीवी फुटेज को नव पदस्थ थाना प्रभारी सुरक्षित रख पाते हैं या फिलहाल जिले में थाना प्रभारियों के ऊपर भी हुक्म चला रहे प्रधान आरक्षक के कहने पर उसे डिलीट कर देते हैं मिटा देते हैं।।

प्रधान आरक्षक जिले में थाना प्रभारियों से भी ऊपर,उन्हे मिला हुआ है विशेष अधिकार,क्या यह अधिकार है नियमानुसार

सूत्रों की माने तो सुपर कॉप प्रधान आरक्षक जो अभी जिले के सभी थाना प्रभारियों से ऊपर रहकर काम कर रहे हैं और जिनका आदेश थाना प्रभारियों को भी मानना मजबूरी है, क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार इसके लिए मिला हुआ है। प्रधान आरक्षक को मिला विशेष अधिकार क्या नियमानुसार है क्या विभाग में सुपर टीम गठन का कोई नियम है यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे कोरिया जिले में अभी पुलिस विभाग एक प्रधान आरक्षक की गिरफ्त में है और वह जैसा जब जो करना चाहे वह स्वतंत्र है और उसके विरुद्ध हुई किसी शिकायत पर भी विभाग मौन रहता है माना जाता है वह अधिकारियों की दुखती रग से वाकिफ है और उसी का फायदा उठाकर वह अपनी मनमानी लगातार कर रहा है।

आखिर पुलिस विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध हुई शिकायतों की जांच को लेकर क्यों हो जाता है मौन,जांच के नाम पर केवल मामले को दबाने में विश्वास

पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों की होने वाली शिकायतों को लेकर जांच की ही बात केवल करता है,पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों को बचाने हर स्थिति में तैयार रहता है जबकि मामला किसी और से जुड़ा हो वह तत्काल कार्यवाही करता है। पुलिस विभाग का काम है कानून की मौजूदगी साबित करना लेकिन अपने ही विभाग के कर्मचारियों की मनमानी वह नहीं रोकता और जब शिकायत सामने आती है वह जांच की बात कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों है,क्या पुलिस विभाग जो स्वयं जांच और कार्यवाही के लिए किसी अपराध या शिकायत की अधिकृत है और जब शिकायत उसके ही कर्मचारी की हो जाए वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है और दोषी पुलिसकर्मी को बचाता है यही सही है। वैसे पुलिस को निष्पक्ष होने का शपथ मिला हुआ होता है लेकिन अपने मामलो में उनकी निष्पक्षता कहां जाति है यह बड़ा सवाल है।

क्या जिले के पुलिस थाने अपराध रोक पाने में हो रहे हैं असफल, क्या इसीलिए बना है स्पेशल दस्ता,यदि ऐसा है तो पुलिस थानों की क्या है उपयोगिता?

कोरिया जिले में पुलिस विभाग ने स्पेशल दस्ता गठित किया है जो प्रत्येक थाना क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से खुद कार्यवाही कर रहा है, यह दस्ता किसी भी थाना क्षेत्र में बिना थाना प्रभारी की अनुमति कहीं भी छापामार कार्यवाही करता है साथ ही यह लगातार थाना क्षेत्र के प्रत्येक मामलों में आगे रहकर काम करता है,अब ऐसे में सवाल यह उठता है की क्या जिले के पुलिस थाने साथ ही वहां के पुलिसकर्मी अपने थाना क्षेत्र में कार्यवाही कर पाने में असफल साबित हो रहे हैं, क्या वह क्षेत्र में अपराध पर अवैध कार्यों पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रहें हैं? इसीलिए स्पेशल दस्ता बनाया गया है,यदि ऐसा है तो फिर पुलिस थानों की उपयोगिता क्या है यह बड़ा सवाल है। वैसे स्पेशल दस्ता किसी भी थाना क्षेत्र में उस थाने के पुलिसकर्मियों की बिना जानकारी लगातार कार्यवाही कर रही है और जिससे यह भी साबित हो रहा है की पुलिस थाने नाकाम हैं कार्यवाही करने में।

क्या स्पेशल दस्ता कोयले और कबाड़ के अवैध कारोबार पर भी अंकुश लगाएगा,इन कारोबारों पर कभी अंकुश लगा पान में पुलिस थाने रह चुके हैं नाकाम

जिले का स्पेशल दस्ता क्या जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में होने वाले कोयला और कबाड़ के अवैध कारोबार पर भी अंकुश लगाएगा यह भी एक बड़ा सवाल है। आज तक इन कारोबारों पर कोई पुलिस थाना अंकुश नहीं लगा सका है अब देखना है की यह स्पेशल दस्ता किस तरह इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाता है,या इस मामले में जिसमे सबकुछ सफेदपोशों की निगरानी में होता है वह कभी बंद नहीं होने वाला कारोबार बना रहेगा।

रात के बारह बजे दिन निकलता है सुबह में छः बजे रात होती है,आजकल ऐसा ही कुछ नगरपालिका बैकुंठपुर में हो रहा है...

- रामानुज मिनी स्टेडियम में 36 लाख की लागत से जारी हाई मास्क लाइट का काम रात के 12 बजे शुरू होता है
- कहीं भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाने तो नहीं होता रात के अंधेरे में 36 लाख का यह काम
- स्टेडियम के लिए मिली यह सौगात कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए उठ रहा सवाल

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,11 अगस्त 2023 (घटती-घटना)। कभी पुराने समय में एक फिल्मी गाना सुना था हमने जिसके बोल थे रात के बारह बजे दिन निकलता है सुबह के छः बजे दिन निकलता है आजकल ऐसा ही कुछ बैकुंठपुर नगरपालिका में भी हो रहा है जहां खिलाड़ियों के लिए मिनी स्टेडियम रामानुज स्कूल प्रांगण में हाई मास्क लाइट का काम हो रहा है जो रात को 12 बजे शुरू किया जाता है वहीं दिन के उजाले में यह काम बंद रहता है।

रात के समय में जारी यह निर्माण कार्य किस कारण रात के अंधेरे में किया जाता है यह बड़ा सवाल है।कहीं इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार तो नहीं यह बड़ा सवाल है। खिलाड़ियों की सुविधा के मद्देनजर स्थानीय विधायक ने अपनी निधि से 36 लाख रुपए हाई मास्क लाइट लगाने उपलब्ध कराया है वहीं यह निर्माण कार्य रात में संपन्न किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य सुबह या दिन के उजाले में भी किया जा सकता है लेकिन इसका कार्य रात के अंधेरे में होना कई सवाल खड़े करता है।

रात के अंधेरे में जारी कार्य की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल

हाई मास्क लाइट का कार्य रात के अंधेरे में किया जा रहा है। रात के अंधेरे में ही कंक्रीट कार्य भी संपन्न हो रहा है,अब रात में हो रहे कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता साथ ही उसकी उचित निगरानी किस तरह संभव हो रही है यह प्रश्न लगातार उठ रहा है। कंक्रीट का कार्य दिन के उजाले में सही तरीके से हो सकता है ऐसा माना जाता है लेकिन इस मामले में पूरा कार्य रात के अंधेरे में जारी है।।

कहीं बड़े भ्रष्टाचार की तैयारी तो नही,रात के अंधेरे में इसलिए ही किया जा रहा कार्य

सवाल यह भी उठता है की कहीं बड़े भ्रष्टाचार की तैयारी तो नही है पूरे निर्माण कार्य में इसलिए रात के अंधेरे में निर्माण किया जा रहा है।यदि ऐसा है तो यह खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर है वहीं यह शहर वासियों के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि जिनके लिए यह निर्माण हो रहा है यदि उन्हे गुणवत्तावहीन निर्माण मिलेगा तो उसका भविष्य कितना होगा यह सोचने वाली बात है।

कोषालय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन

7 से 11 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर किया काम,दूसरे चरण का आंदोलन 26 से

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,11 अगस्त 2023 (घटती-घटना)। पांच सूत्रीय मांगो को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कोषालय कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्य सचिव छत्तीसगढ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है,मांग पूरी न होने की स्थिति में क्रमबद्व तरीके से आंदोलन की बात कही गई है। कोषालय कर्मचारियों ने प्रथम चरण के आंदोलन के तहत 7 अगस्त से 11 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर काम किया और अंतिम दिवस ज्ञापन सौंपकर पहले चरण का आंदोलन समाप्त किया। उक्ताशय की जानकारी देते हुए कोषालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राहुल मिश्रा ने बताया कि हमारे संगठन द्वारा पूर्व में शासन को विधिवत 15 दिवस पूर्व प्रेषित किया गया था, शासन द्वारा 15 दिवस के बाद भी उक्त मांगों पर कोई पहल नही किये जाने के कारण प्रदेश के समस्त कोषालयों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा कराने 7 से 11 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर काम करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके बाद 5 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन मुख्य सचिव छत्तीसगढ के नाम कलेक्टर कोरिया के माध्यम से सौंपकर मांग पूरा करने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में कोषालय कर्मचारी संघ ने कहा है कि अधीनस्थ लेखा सेवा में कोषालयीन लिपिकों से परीक्षा के माध्यम से 20 प्रतिशत एवं कोषालयीन लिपिकों को पदोन्नति के माध्यम से 20 प्रतिषत पद

आरक्षित किया जाए, कोषालयीन लिपिकों की वेतन विसंगति के संबंध में संचालक कोष,लेखा एवं पेंशन,इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 3281 दिनांक 24.07.2018 एवं माननीय शिवकुमार डहरिया मंत्री छत्तीसगढ शासन नोटशीट क्रमांक 3591 दिनांक 13.03.2020 प्रस्ताव के अनुसार किया जाए,चतुर्थ श्रेणी कोषा लयीन कर्मचारियों के ग्रेड पे 1300 के स्थान पर ग्रेड पे 1800 किया जाए,कोषालयीन कर्मचारियों का तृतीय समयमान वेतनमान प्रदाय किया जाए एवं सहायक ग्रेड 02 से लेखा सहायक के 42 रिक्त पदों पर पदोन्नति किया जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि इसके बाद भी मांग पूरी नही है तो कोषालय कर्मचारी संघ द्वारा द्वितीय चरण में 26 अगस्त को प्रदेश के सभी संभागीय स्तर पर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करते हुये शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। ज्ञापन सौंपते वक्त जिलाध्यक्ष राहुल मिश्रा के साथ,अनुराग सोनी,वीरेन्द्र पटेल,भगवानी राम ठाकुर, श्यामबिहारी साहू,रश्मि लकड़ा, राशिदा बानो, शारदा पोर्ते, रामनेवाज, शिव पाल, विल्सन किंडो, सितालो भगत आदि कर्मचारी उपस्थित थे।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष हितेश ने जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,11 अगस्त 2023 (घटती-घटना)। भाजयुमो जिलाध्यक्ष हितेश ने जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज, आपको बता दें कि आज भाजयुमो जिला अध्यक्ष हितेश प्रताप सिंह एवं उनकी भाजयुमो के साथीयों के द्वारा कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया केंद्र सरकार की मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना गांव गरीब तक नल जल योजना के माध्यम से जल की व्यवस्था घर घर तक कराई जा रही आरोप लगाते हुए, हितेश ने कहा की इसमें यह निकम्मी और भ्रष्ट कांग्रेसी भूपेश की सरकार भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है सत्ता पर बैठे लोग अधिकारियो ठेकेदारों के साथ मिल के पैसों का बंदरबांट कर मिल जुल कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे ग्राम पंचायत में चल रहे नल जल योजना के अंतर्गत कार्य में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है जब गांव वालो ने उनके खिलाफ विरोध किया अपने स्तर से तो कोई सुनवाई नहीं हुई यह बात भाजायुमो के जिला अध्यक्ष हितेश प्रताप सिंह के कानों तक पहुंची और वह बंजारीडाड के दौरे पर थे इसके तत्काल सूचना के बाद उक्त जगह पर जाकर हितेश सिंह ने चल रहे कार्य का दौरा किया जायजा लिया और वहां परपाया की पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का खेल सत्ता के आड़ में किया जा रहा है जिसकी शिकायत कोरिया कलेक्टर को तत्काल अपने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन दिया यह भी कहा की उक्त कार्य की पूर्ण रूप से जांच होने के पश्चात ही कार्य को आगे बढ़ाया जाए साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई जगहों पर बहुत घटिया निर्माण कार्य

हुआ है उसका भी पर्दा फास जल्द ही होगा और उक्त विभाग के कार्यों की जांच हो अन्यथा विभाग का कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करेगी भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरिया ज्ञापन देते समय भाजयुमो के महामंत्री कुणाल जायसवाल, अजय तिवारी, शरद सिंह, संजय दुबे, रॉबट हनी सामिल रहे।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ.ग.

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /.../अ-20(3)/2022-23

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि सीताराम अग्रवाल आ0 टेकचंद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी चर्चरोड केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा के द्वारा अपने स्वामित्व मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर-3 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 1137/1, 1138/2 रकबा क्रमशः 0.01, 0.01 एकड़ एवं भूखण्ड क्रमांक 1139/1, 1139/15, 1139/19 रकबा क्रमशः 0.23 3/4,0.25, 0.20 एकड़ भूमि को अनावेदकगण राम कृष्ण गोयल आ0 राजीव अग्रवाल, राधे कृष्ण गोयल आ0 राजीव अग्रवाल निवासी चर्च रोड केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर के पक्ष में दान किये जाने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दाया अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता को माध्यम से दिनांक-28/ 08/2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दाया-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनाक- 08/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदुद्रा से जारी।

सील — **नजूल अधिकारी अम्बिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ.ग.

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /.../अ-20(3)/2022-23

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि आवेदिका शमीमा बेगम पत्नी कलीमुल्ला कुरैशी उम्र लगभग 58 वर्ष जाति कसाब (मसुलमान) निवासी मायापुर, अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 1583/2, 1584 रकबा क्रमशः 0.10, 0.27 एकड़ के नजूल अभिलेखों से खातेदार कलीमुल्ला कुरैशी आ0 मो0 सिद्दीकी कुरैशी निवासी मायापुर का नाम विलोपित कराते हुए हिब्बानामा के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ हिब्बानामा,नजूल मेन्टेनेन्स खसरा एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दाया अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता को माध्यम से दिनांक-11/ 09/2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दाया-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनाक-11/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदुद्रा से जारी।

सील — **नजूल अधिकारी अम्बिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ.ग.

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /.../अ-20(3)/2022-23

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि आवेदक अब्दुल आकीब आ0 स्व0 अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी भैयाथान रोड सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ0ग0 एवं अन्य-02 के द्वारा अपने संयुक्त स्वामित्व की मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर -04 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 1980/27 रकबा 0.10 एकड़ भूमि को रूपये 21,45000-00 में अनावेदक मयंक कुमार मिश्रा आ0 संतोष मिश्रा निवासी भट्ठी रोड केदारपुर अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के पक्ष में बिक्रय अनापत्ति प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दाया अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता को माध्यम से दिनांक- 11/ 09/2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दाया-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनाक-11/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदुद्रा से जारी।

सील — **नजूल अधिकारी अम्बिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ.ग.

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /.../अ-20(3)/2022-23

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि आवेदक अब्दुल जूनैद आ0 स्व0 अब्दुल रशीद जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास महगवा थाना व तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ0ग0 एवं अन्य-06 के द्वारा अपने संयुक्त स्वामित्व की मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर -04 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 1980/28 रकबा 0.05 एकड (1200 वर्गफीट)भूमि/मकान को रूपये 18,15,00-00 में अनावेदक मयंक कुमार मिश्रा आ0 संतोष मिश्रा निवासी भट्ठी रोड केदारपुर अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के पक्ष में बिक्रय अनापत्ति प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दाया अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता को माध्यम से दिनांक- 11/ 09/2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दाया-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनाक-11/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदुद्रा से जारी।

सील — **नजूल अधिकारी अम्बिकापुर**

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)अम्बिकापुर,जिला सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /.../अ-2/2022-23

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दुर्गावती पत्नी विजयनन्द जाति गोंड निवासी ग्राम/नगर मणीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा, छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम मणीपुर तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 196/10 रकबा 0.012 हे0 भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, सेटलमेन्ट, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएवं उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 28/08/2023 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के काय्रालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

विश्व आदिवासी दिवस के दिन

आदिवासी युवा नेता के घर पहुंचे मुख्यमंत्री

पंगत में बैठ परंपरागत आदिवासी व्यंजनों का उठाया लुत्फ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन अनूपपुर जिले के प्रवास में रहे। इस दौरान उन्होने रोड-शो, जन चौपाल, मां नर्मदा के दर्शन पूजन के साथ पुष्पराजगढ़ के पोडक़ी में जनसंवाद, खटिया चौपाल जैसे आयोजन किये गए। फिर रात्रि कालीन भोजन के लिये वे पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के युवा आदिवासी नेता हीरा सिंह श्याम के गृह ग्राम अमगंवा जा पहुंचे और वहां बेहद सहज सरल रूप से पंगत में बैठकर सभी के साथ भोजन ग्रहण किया..

-अरविंद द्विवेदी-
अनूपपुर, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

मुख्यमंत्री ने अनूपपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है जिसमें एनडीबी योजना के तहत 5.50 करोड़ लागत से निर्मित तिपान पुल का लोकार्पण, रोड-शो जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ा रहा साथ ही पुष्प वर्षा के माध्यम से नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जगह-जगह स्वागत स्थल बनाये गये थे, लाड़ली बहनों ने कलश यात्रा निकाली। इधर सजे मंच में लोक कलाकारों द्वारा नृत्य वादन पेश किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने भी साझेदारी की। तत्पश्चात 310 करोड़ 65 लाख 57 हजार की लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया साथ ही 5600 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले ताप विद्युत परियोजना चचाई का भी शिलान्यास किया।

अचानक पहुंचे हीरा के घर

9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिले के प्रवास में आये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों की जो जानकारी जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई थी उसमें सीएम शिवराज का ग्राम अमगंवा जाना नही दर्शाया गया था। शायद यही वजह है कि जानकार बता रहे हैं कि हीरा सिंह श्याम के गृह ग्राम में मुख्यमंत्री का अचानक कार्यक्रम उनकी इच्छा अनुरूप बनाया गया। तब ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गर्म जोशी से स्वागत करते हुये भोजन का आमंत्रण दिये। जिसे शिवराज द्वारा सहर्ष स्वीकार कर पंगत में बैठ भोजन ग्रहण किये, परोसे गये भोजन में अधिकांश आदिवासियों का परंपरागत व्यंजन जिसमें मक्के की रोटी, भाजी, कोदो की खीर व चावल के साथ दाल परोसी गई।

परंपरागत तौर से सम्मान

विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के रात्रि करीब 9 से 10 के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला पुष्पराजगढ़ के ग्राम अमगंवा निवासी युवा नेता हीरा सिंह श्याम के घर पहुंचा। जहां सर्वप्रथम हीरा सिंह के पिता ने आदिवासी परंपरा अनुसार पैर धुलाये, फिर आरती उतारी गई। उसके बाद घर के आंगन में रखे तखत में आदर सत्कार के साथ उन्हे बैठाया, जहां हीरा सिंह, पत्नी व अपनी बेटी के साथ मुख्यमंत्री से मिले। उस दौरान सीएम ने युवा नेता की बेटी को अपने गोद में लिया और पहली बार मिल रहा हूं कहते हुये उपहार भेंट की। इसके साथ हीरा सिंह का पूरा परिवार, ग्राम वासियों से मिलना व परिचय लेने का क्रम चलता रहा। पूरे दिन व्यस्तता की थकावट दूर करने घर के अंदर बने स्नान गृह में हाथ मुंह धोकर एक बार फिर सबसे रूबरू हुये। इधर पंगत में लगाये गये भोजन ग्रहण करने के आग्रह मिलते ही सभी के साथ बैठकर बड़े चाव से भोजन का लुत्फ उठाया।

राजनीति के हैं अलग मायने

वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हीरा सिंह के घर जा वहां भोजन करना प्रत्यक्ष दर्शियों को आम घटना ही लगी। चूंकि मुख्यमंत्री बेहद सहज व सरल तौर पर लोगों से मिले, किन्तु राजनीतिक गलियारों में अलग ही कयास लगाये जा रहे हैं। वजह वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव का वर्ष पूर्व से घोषित रहा है, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हीरा सिंह युवा आदिवासी नेता के साथ बेदाग छवि रखते हैं। कम उम्र में ही पहले जिला पंचायत सदस्य फिर जनपद अध्यक्ष चुने गये थे और वर्तमान में बीजेपी के जिला महामंत्री पद पर सेवा दे रहे हैं। मतलब साफ है कि ये टिकट की दौड़ में सामिल ही नही बल्कि प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। ऐसे में सीएम शिवराज का औचक हीरा सिंह के घर जाना विरोधियों के गले की फांस बना दिख रहा है। तभी तो राजनीतिक चर्चाओं का बाजार अलग-अलग सोच व बातों से गुलजार है।

पिकअप और कार के बीच जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौत

-संवाददाता-
कोरबा, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

जिले में उरगा-हाटी मार्ग पर कोडमसरा नाले के पास शुक्रवार दोपहर को पिकअप और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला करतला थाना क्षेत्र का है।जानकारी के मुताबिक, बालको निवासी हैबीकुल कमल अपने साथी आबिद अख्तर के साथ अपनी कार से हाटी की तरफ जा रहा था। कार हैबीकुल चला रहा था वहीं पिकअप उरगा हाटी से करतला की ओर आ रहा था। दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी। दोनों गाड़ियों के बीच उरगा-हाटी मार्ग पर जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पिकअप और कार के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत होने से कार चालक हैबीकुल बुरी तरह से गाड़ी में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई जिसकी जानकारी लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। करतला थाना प्रभारी लालन पटेल तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। करतला थाना प्रभारी ललन पटेल ने बताया कि गाड़ी में फंसे मृतक को काफी मशक्कत से निकाला गया। इसके लिए गैस कटर से कार के हिस्से काटने पड़े। घायल युवक की हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है वहीं हादसे के बाद से आरोपी पिकअप चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

मुख्यमंत्री के सफल कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने व्यक्त किया आभार

-अरविंद द्विवेदी-
अनूपपुर, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने अनूपपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रमण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना अहम योगदान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों एवं जिले की आम जनमानस तथा जिला प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया। जिलाध्यक्ष ने रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, विद्यार्थियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों, पत्रकारों आदि के द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि अनूपपुर जिले की धरती पर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिस तरह से सभी लोगों का सहयोग मिला उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। हर वर्ग के लोगों का जन समर्थन मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार अच्छी सरकार है। शासकीय एकलव्य विद्यालय परिसर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन एवं भू-अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में बड़ी पधारे माताओं बहनों, पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकायो तथा अमरकंटक के प्रवास के दौरान वहां के साधु संतो तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी लोगों के प्रति भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अधिवक्ताओं ने भरी हुंकार, सौंपा ज्ञापन

मांग पूरी न होने पर 25 को निकालेंगे आक्रोश रैली

-संवाददाता-
कोरबा, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दस लाख रुपए मृत्यु दावा राशि देने तथा सामूहिक बीमा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का असर कोरबा में भी दिखा। आन्दोलन के प्रथम चरण में 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। जिसके तहत जिला मुख्यालय में अधिवक्ता संघ में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया द्व जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव नूतन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं से वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे साथ ही अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए मृत्यु दावा राशि और सामूहिक बीमा का लाभ देंगे लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार अपना वादा भूल गई। सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ता एकजुट होकर 11 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत की है। कोरबा सहित प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं से किया गया वादा पूरा करने की मांग की गई है । इसके बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ तो 25 अगस्त को विशाल आक्रोश रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। सितंबर माह से राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा।

कृषि विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान चार केंद्रों में पाई गई खामियां, नोटिस जारी

-संवाददाता-
कोरबा, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

कृषि विभाग द्वारा 10 अगस्त को पाली विकासखंड के चार कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया द्व चारों केंद्र में खाद की भौतिक उपलब्धता सहित अन्य खामियां पाए जाने पर खाद बिक्री पर रोक लगाते हुए संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। उर्वरक निरीक्षक राजेशवरी राय, अनुविभागीय अधिकारी राजेश भारती सहित कृषि विभाग की टीम ने पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम हरदी बाजार, सिरली, बोइदा, उतारदा में संचालित कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिसमे खामियां पाए जाने पर 1. मेसर्स कान्हा कृषि केंद्र सिरली में पीओएस मशीन और भौतिक उपलब्ध खाद में भिन्नता पाए जाने पर नोटिस दिया गया एवं उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु वरिष्ठालय को पत्र प्रेषित किया गया है, 2.मेसर्स नारायण प्रसाद शर्मा ग्राम बोइदा में उर्वरक का भंडारण दर्शित नक्शे में ना करने पर एसएसपी का वितरण प्रतिबंधित करते हुए नोटिस जारी किया गया है. 3. न्यू रमेश ट्रेडर्स लोटना पारा उतरदा में 8 बैग डीएपी बीमा पीओएस मशीन में एंट्री के पाया गया जिसे विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया। पीओएस और उपलब्ध खाद की मात्रा में अंतर के लिए नोटिस जारी कर लाइसेंस निरस्त करने की प्रतिवेदन वरिष्ठलय को प्रेषित किया गया है. 4.मेसर्स यदुराज ट्रेडर्स हरदीबाजार में पीओएस मशीन और उपब्ध खाद की मात्रा का मिलान सही नही पाने पर नोटिस दिया गया साथ ही पीओएस में दर्ज नहीं होने पर 12 बैग यूरिया को प्रतिबंधित करते हुए इन केंद्रों पर कार्यवाही की गई है। उक्त छापामार कार्यवाही जिला उपसंचालक कृषि अजय अनंत एवं कलेक्टर कोरबा के मार्गदर्शन में उर्वरक निरीक्षक राजेशवरी राय, अनुविभागीय अधिकारी राजेश भारती सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों ने बिना लाइसेंस और गलत तरीके से व्यापार कर रहे विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया और लाइसेंस निरस्तीकरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई। कृषि विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से कृषि केंद्र संचालकों में हड़कम्प मच गया है।

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व सांसद ज्योत्सना महंत की अथक प्रयासों हुआ मुमकिन

दर्री बरॉज से बरमपुर तक सड़क के लिए एसईसीएल ने जारी किया स्वीकृति पत्र

-सवाददाता-
कोरबा, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

कोरबा शहर विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के अथक प्रयासों से एसईसीएल प्रबंधन ने लगभग 84 करोड़ की लागत से बनने वाले दर्री बरॉज से बरमपुर तक लगभग 8.20 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण हेतु महाप्रबंधक सिविल ने सहमति पत्र 9 अगस्त को जारी कर दिया है। कोरबा जिला कलेक्टर को संबोधित पत्र में एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के सिविल महाप्रबंधक से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य पर लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत वहन करने के लिए एसईसीएल प्रबंधन ने सहर्ष अनुमोदन प्रदान कर दिया है।पत्र में लिखा गया है कि सड़क निर्माण कार्य दो साल के भीतर पूरा किया जाएगा और इस पर अनुमानित लागत की उपर्युक्त राशि एसईसीएल प्रबंधन की ओर से चार किस्तों में जारी किया जाएगा। सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। पत्र में उन स्थितियों व शर्तो का विवरण दिया गया है जिसके तहत चार किस्तों में एसईसीएल द्वारा सड़क निर्माण लागत का भुगतान जारी किया जावेगा। प्रथम किस्त के तौर पर अनुमानित निर्माण लागत की 20 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रारूप के अनुसार राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अनुमानित लागत या कार्य आदेश मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो, जो व्यय विवरण कार्य की भौतिक स्थिति एवं लोक निर्माण विभाग, कोरबा से जारी कार्यादेश की प्रमाणित प्रति के आधार पर होगा, जारी किया जावेगा। तीसरी किस्त के रूप में अनुमानित लागत या कार्य आदेश मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति और व्यय विवरण एवं कार्य की भौतिक स्थिति पर आधारित होगा, जबकि जारी की जाने वाली चौथी या अंतिम किस्त के रूप में शेष बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा जो काम पूरा होने के बाद और राज्य सरकार से प्रमाणित होगा और अनुमानित लागत या कार्य आदेश मूल्य या कार्य के समापन मूल्य तक सीमित, जो भी सबसे कम हो, राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है एवं निर्धारित प्रारूप के अनुसार. व्यय विवरण व कार्य की भौतिक स्थिति के अधीन होगा। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विकास के प्रति सदैव सजग राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व ज्योत्सना चरणदास महंत ने एसईसीएल प्रबंधन से उक्त सड़क निर्माण कार्य के लिए लगातार दबाव बनाया। इसी सिलसिले में राजस्व मंत्री व सांसद ने एसईसीएल प्रबंधन के साथ अनेक बैठकों में शामिल होकर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा। क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है कि जयसिंह अग्रवाल व ज्योत्सना महंत की मेहनत रंग लाई और एसईसीएल के सौजन्य से दर्री बरॉज से बरमपुर का आवागमन सहज व सुलभ हो पाना संभव हो सकेगा।

एनटीपीसी कोरबा नैगम सामाजिक दायित्व के तहत आयोजित तीरंदाजी प्रतिभा खोज शिविर

-संवाददाता-
कोरबा, 11 अगस्त 2023
(घटती घटना)

एनटीपीसी कोरबा नैगम सामाजिक दायित्व के तहत तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी कोरबा सीएसआर द्वारा प्रतिभा खोज शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कोरबा जिले के चार अलग-अलग क्षेत्रों देवपहरी, सतरेंगा, अजगरबहार और सोनपुरी में एक सप्ताह के लिए आयोजित किया गयद्व द्व इस कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के लगभग 200 लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया द्यडुड्डुह्लद्ध द्धद्ब इस प्राचीन खेल में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। तीरंदाजी शिविर के दौरान राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी श्री भरत यादव ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया तथा खेल की बारीकियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। दिनांक 10.08.2023 को शिविर के समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक प्रदान किये गये। इस समापन समारोह में एनटीपीसी कोरबा के सीएसआर अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और ग्रामीण उपस्थित थे। इस शिविर का उद्देश्य युवाओं के कौशल और प्रतिभा को विकसित करना और प्रतिभा खोज शिविर के माध्यम से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत प्रतिभाशाली उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है।

अमेरिका में डब्ल्यूआई पर भारी पड़ी है टीम इंडिया

» आज खेला जाएगा सीरीज का चौथा मैच

नई दिल्ली,11 अगस्त 2023। वेस्टइंडीज के विरुद्ध पांच मैचों की टी-20 सीरीज के अंतिम दो मैच अब अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। शुरुआती दो मुकाबले गंवाने के बाद तीसरा टी-20 मैच जीतकर भारत ने सीरीज में वापसी की थी और अब उसे वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार छठी सीरीज जीतने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे।

वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी

अगर बात करें भारतीय टीम के अमेरिका में प्रदर्शन की तो वेस्टइंडीज इंडिया वेस डब्लूआई के विरुद्ध उसका पलड़ा भारी रहा है। 2016 से भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई तीन सीरीज के छह मैचों का आयोजन फ्लोरिडा के लाडरहिल में किया गया। इनमें से भारत ने चार मैच जीते, जबकि एक में हार मिली। एक मैच बेनतीजा रहा।

पहला आईसीसी से मान्यता प्राप्त स्टेडियम

लाडरहिल अमेरिका का पहला आइसीसी से मान्यता प्राप्त स्टेडियम है। 2019 दौरे पर भारत ने यहां दो और 2022 में भी दो मैच खेले थे और चारों में जीत दर्ज की थी। ऐसे में पिछले प्रदर्शन को देखें तो भारत यहां सीरीज जीतने का दावेदार है, लेकिन उसके लिए हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा।

आरंभिक जोड़ी चिंता का विषय

सीरीज में आरंभिक जोड़ी का न चलना भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। अब तक खेले गए तीनों मैचों में आरंभिक जोड़ी टीम को ठोस शुरुआत नहीं दिला सकी है। शुरुआती दो मैचों में शुभमन गिल और इशान ने पहले विकेट के लिए पांच और 18 रन की ही साझेदारी की थी। इसके बाद टीम प्रबंधन ने तीसरे मैच में इशान की जगह यशस्वी जायसवाल को गिल के साथ भेजा, लेकिन ये जोड़ी भी प्रभावित नहीं कर सकी और सिर्फ छह रन ही बना सकी। ऐसे में अगर भारतीय टीम को सीरीज अपने नाम करनी है तो आरंभिक जोड़ी को रन बनाने होंगे।

भारतीय टीम मियामी पहुंची

टीम इंडिया मियामी पहुंच गई। यहां के लाडरहिल में शनिवार को सीरीज का चौथा टी-20 मैच खेला जाएगा। बीसीसीआइ ने टीम इंडिया का वीडियो साझा किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ी फ्लाइट में नजर आ रहे हैं और इसके बाद वे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इस दौरान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभमन गिल और युजवेंद्रा सिंह चहल दिलचस्प अंदाज में नजर आए। गिल कुछ खाते नजर आए। उनके साथ गेंदबाज आवेश खान, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह भी दिखे।

पारालुएलो के गोल से स्पेन महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में

वेलिंगटन ,11 अगस्त 2023। सलमा पारालुएलो के अतिरिक्त समय में किये गये गोल की मदद से छठी रैंकिंग पर काबिज स्पेन ने शुक्रवार को यहां नीदरलैंड को 2-1 से हराकर पहली बार महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दो यूरोपीय मजबूत टीमों के बीच कड़े नॉकआउट मुकाबले में पारालुएलो ने 111वें मिनट में विजयी गोल दागा। नीदरलैंड की टीम चार साल पहले फ्रांस में फाइनल में अमेरिका से हार गयी थी और अब दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। मारियोना कालडेंटी ने 81वें मिनट में गोल कर स्पेन को 1-0 से बढ़त दिलायी। नियमित समय के अंतिम 10 मिनट में नीदरलैंड की डिफेंडर स्टेफानी वान डर ग्राफ्ट 'खलनायिका' से 'नायिका' बन गयीं जिन्होंने अपनी टीम के लिए बराबरी गोल दागा।

हांगझोऊ को 2026 तक बीडब्ल्यूएफ फाइनल की मेजबानी मिली

कुआलालंपुर ,11 अगस्त 2023। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने चीन के हांगझोऊ को अगले चार वर्षों के लिए सीजन के अंत वाले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स का मेजबान शहर नियुक्त किया है। पिछले साल के संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण ग्वांगझोउ से बैंकॉक में स्थानांतरित करने के बाद बैडमिंटन का सीजन-एंडिंग इवेंट एक चीनी शहर में लौट आया है। बैडमिंटन की विश्व नियामक संस्था ने एक बयान में कहा, बीडब्ल्यूएफ को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रतिष्ठित एचएसबीसी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल पूरे चक्र के लिए हांगझोऊ में होगा। हांगझोऊ 19वें एशियाई खेलों का घर है और अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के शोपीस इवेंट के लिए एकदम सही स्थान है। 2023 बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल शहर में स्थगित 2022 एशियाई खेलों के समापन के दो महीने से अधिक समय बाद 13 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाला है।

2023 से शुरू होकर बीडब्ल्यूएफ ने 31-इवेंट वाले नए वर्ल्ड टूर कैलेंडर का अनावरण किया, जिसमें सुपर 1000, सुपर 750 और सुपर 500 टूर्नामेंट होंगे, जो खिलाड़ियों के लिए अधिक पुरस्कार राशि के अवसर लाएंगे।

इस चक्र के लिए हमारे प्रमुख बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के मेजबान के रूप में चीन के हांगझोऊ की पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बैडमिंटन अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी और प्रशंसकों की संख्या के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में से एक है।

बयान में कहा गया है, शानदार खेल का बुनियादी ढांचा और विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन का अनुभव हमारे फाइनल के लिए एक आदर्श मेजबान है।

बीडब्ल्यूएफ के महासचिव थॉमस लुंड ने कहा, हम टूर के शीर्ष आठ खिलाड़ियों और प्रत्येक वर्ग की जोड़ियों के हजारों उत्साही प्रशंसकों के सामने गौरव के लिए लड़ने की उम्मीद करते हैं। अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में आयोजित होंगे।

खेल मंत्रालय ने पहलवानों को विशेष ट्रेनिंग शिविर और प्रतियोगिता के लिए रोमानिया भेजा

नई दिल्ली ,11 अगस्त 2023। एशियाई खेलों की टीम में शामिल छह पहलवान खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) को सहायता देने की योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग शिविर और प्रतियोगिता के लिए तीन सहयोगी स्टाफ सदस्यों के साथ रोमानिया के लिए रवाना हुए।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरे के दौरान टीम 18 से 20 अगस्त तक इयोन कोर्नियानू और लाडिस्लाऊ सिमोन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी।

विज्ञप्ति के अनुसार यह अंतरराष्ट्रीय दौरा 15 दिन का होगा जिसमें टीम की ट्रेनिंग का पूरा खर्चा, टिकट और ठहरने की व्यवस्था, वीजा का खर्च और आउट ऑफ पॉकेट' भत्ते का पूरा खर्चा उठाया जायेगा।

एशियाई खेल 23 सितंबर से आठ

खेल मंत्रालय

रोमानिया दौरे पर गये ग्रीको रोमन पहलवान :

ज्ञानेंदर (60 किग्रा), नीरज (67 किग्रा), विकास (77 किग्रा - खेलो इंडिया एथलीट), सुनील कुमार (87 किग्रा - टॉप्स एथलीट), नरिंदर चीमा (97 किग्रा - खेलो इंडिया एथलीट) और नवीन (130 किग्रा)।

हॉकी इंडिया ने हॉकी इंडिया लीग के लिए वित्तीय मॉडल को मंजूरी दी

चेन्नई ,11 अगस्त 2023। हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड ने हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के लिए अपने वाणिज्यिक एजेंट द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मॉडल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी, जिससे लीग के पुनरुद्धार के लिए एजेंसी के लिए औपचारिक रूप से बाजार में उतरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

यहां कार्यकारी बोर्ड की 100वीं बैठक में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा, पिछले महीने हमने अपनी मार्केटिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तावित एचआईएल पुनरुद्धार योजनाओं की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई थी और आज कार्यकारी बोर्ड ने हॉकी इंडिया लीग के लिए बिग बैंग मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मॉडल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी और हम इस निर्णय पर पहुंचे। एजेंसी को आधिकारिक तौर पर हॉकी इंडिया लीग के लिए बाजार में कदम रखने दें। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य बहुत उच्च गुणवत्ता वाली हॉकी का उत्पादन करना है, जो खेल को और भी ऊपर उठाने में मदद करेगा।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने राष्ट्रपति की भावनाओं को दोहराते हुए कहा, मेरा मानना है कि हॉकी इंडिया लीग न केवल भारत में, बल्कि दुनियाभर में खेलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ियों को भी प्रतिस्पर्धा करके अपने खेल को ऊपर उठाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम और एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) के अध्यक्ष फुमियो ओगुरा भी शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।

कार्यकारी बोर्ड ने चीन के हांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले आगामी एशियाई खेलों सहित कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की।

केन्या से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं:अनिल कुंबले

नई दिल्ली ,11 अगस्त 2023। भारत के महान लेग स्पिनर और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने खुलासा किया कि उनके खेल करियर में, भारत-पाकिस्तान मैचों का प्रचार इतने उच्च स्तर पर था कि अगर टीम केन्या से हार भी जाती तो प्रशंसकों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ़ नहीं।

भारत 2 सितंबर को कैंडी के पल्लेकेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 50 ओवर के एशिया कप 2023 के ग्रुप चरण में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। यदि भारत और पाकिस्तान सुपर फोर चरण में पहुंचते हैं, तो उनका कोलंबो में आमना-सामना होना तय है। भारत और पाकिस्तान पुरुष वनडे विश्व कप के लीग चरण में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे।

कुंबले ने बेंगलुरु में अनुभवी क्रिकेट प्रशासक अमृत माथुर द्वारा लिखे गए संस्मरण पिचसाइड के लॉन्च के दौरान कहा, हमारे समय में, यह शब्द था 'केन्या से भी हारें लेकिन पाकिस्तान से नहीं। कुंबले, जो 2016 से 2017 तक भारत के मुख्य

कोच भी थे, को 1999 में नई दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन देकर ऐतिहासिक 10 विकेट लेने के लिए याद किया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ 34 एकदिवसीय मैचों में, कुंबले ने 54 विकेट लिए हैं। मैं 10 विकेट लेने के बारे में सोचकर मैदान पर नहीं गया था, हालांकि यह किसी भी गेंदबाज का सपना होता है। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ अगले टेस्ट मैच, कोलकाता में एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप में, मैं एक विकेट लेने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उन्होंने कहा, यह आपके लिए क्रिकेट का खेल है। इस कार्यक्रम में कुंबले के अलावा भारत के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, साथ ही पूर्व भारतीय विकेटकीपर और 1983 वनडे विश्व कप विजेता टीम के सदस्य सैयद किरमानी मौजूद थे। कुंबले ने अपने 18 साल के अंतर्राष्ट्रीय खेल करियर को 132 मैचों में 619 विकेट के साथ भारत के लिए टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले और कुल मिलाकर चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समाप्त किया। 271 वनडे मैचों में उन्होंने 337 विकेट लिए।

आलोचकों के मुंह पर लगाया ताला

नई दिल्ली ,11 अगस्त 2023। फटाफट क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना खेलने से क्रिकेट के फैंस उनके करियर का अंतिम पड़ाव मान रहे हैं। पिछले साल टी-20 विश्व कप के बाद से रोहित और कोहली टी-20 सीरीज से बाहर चल रहे हैं। करियर खत्म होने को लेकर उठ रहे सवालों पर अब रोहित शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने टी-20 ना खेलने के पीछे की वजह बताई है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को रोहित शर्मा ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। अपने और विराट के टी-20 मैच ना खेलने के सवाल पर दो टूट जवाब दिया। रोहित ने कहा कि पिछले साल सीनियर खिलाड़ी टी-20 विश्व कप के कारण ज्यादा वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था और इस साल भी वनडे विश्व कप के साथ ऐसा ही कर रहे हैं।

रोहित शर्मा ने दिया आलोचकों को जवाब

रोहित ने कहा, पिछले साल भी हमने यही किया था, टी-20 विश्व कप था, इसलिए हमने वनडे क्रिकेट ज्यादा नहीं खेला। अब भी हम वही कर रहे हैं, वनडे विश्व कप है, इसलिए हम टी-20 नहीं खेल रहे हैं। रोहित ने आगे कहा, यह विश्व कप वर्ष है; हम सभी को तरोताजा रखना चाहते हैं; पहले से ही हमारी टीम में इतनी चोटें थीं कि अब मुझे चोटों से डर लगता है।

दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारियां 2 का फर्स्ट लुक आउट

साल 2014 में रिलीज हुई हिमांश कोहली और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म यारियां बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब पूरे 8 साल बाद फिल्म का सीक्वल रिलीज हो रहा है, जिसका नाम है यारियां 2। हालांकि अब यारियां 2 की स्टारकास्ट पूरी तरह से बदल गई है। फिल्म में अब हिमांश कोहली और रकुल प्रीत सिंह की जगह एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार, पर्ल वी पुरी और एक्टर मिजान जाफरी लीड रोल में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म यारियां 2 का पोस्टर सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं तो वहीं एक्टर पर्ल वी पुरी दुल्हा बने हुए हैं। तो वहीं मिजान जाफरी भी पोस्टर में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि दिव्या खोसला कुमार ने पर्ली वी पुरी और मिजान जाफरी दोनों के कंधों पर अपने हाथ रखे हुए हैं। इसके साथ ही पोस्टर में दिव्या स्मोकिंग कर रही हैं। फिल्म का पोस्टर बहुत वाइब्रेंट है लग रहा है। यारियां 2 का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दिव्या खोसला कुमार ने कैप्शन में लिखा, अपनी मां के आशीर्वाद से, मैं आप सभी के साथ अपनी फिल्म का पोस्टर साझा कर रहा हूं। यारियां 2 फिल्म को राधिका राव और विष्णु सापरु ने डायरेक्ट किया है। बता दें कि दिव्या खोसला कुमार, पर्ल वी पुरी और मिजान जाफरी के अलावा फिल्म में यश दासगुप्ता, अनस्वरा रंजन, वरीना हुसैन और प्रिया प्रकाश वारियर जैसे सितारे भी इस फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है।

व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस पहन पूजा हेगड़े ने इंटरनेट पर लगाई आग

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े आए दिन अपने फैशन स्टेटमेंट्स से फैंस को अपने हुस्न का कायल करती रहती हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं तो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हालांकि इन तस्वीरों में एक बार फिर से उनकी स्टाइलिश अदाएं देखकर फैंस मदहोश हो गए हैं। साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हमेशा अपनी बोल्ड और ग्लैमरस फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट करती रहती हैं। एक्ट्रेस ने बेहद कम समय में लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली है। अब हाल ही में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें फैंस के बीच शेयर की हैं। इन तस्वीरों में पूजा हेगड़े ने व्हाइट कलर की सिंगल स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई है। एक्ट्रेस अपने इस लुक में बेहद ही गॉर्जियस नजर आ रही हैं। साथ ही फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ओपन कर्ली हेयर और लाइट मेकअप कर के एक्ट्रेस ने अपने इस आउटलुक को कंप्लीट किया है। पूजा हेगड़े सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट काफी लंबी है। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं तो फैंस उनकी फोटोज पर जमकर लाइक करते हैं।

आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का फनी पोस्टर रिलीज

आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे ने पहली बार ड्रीम गर्ल 2 पर एक साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया है. खबर की घोषणा के बाद से वे सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि दर्शक उन्हें स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह फिल्म 2019 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रीम गर्ल का सीक्वल है, जिसमें आयुष्मान और नुसरत भरुचा ने अभिनय किया था. फिल्म के टीजर और ट्रेलर के बाद आज मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है.

आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का लेटेस्ट पोस्टर आज निर्माताओं द्वारा रिलीज किया गया. कुछ मिनट पहले, आयुष्मान खुराना ने एक अनोखा पोस्टर जारी किया था जिसमें वह पूजा के रूप में नजर आ रहे हैं. वह पिंक लहंगा पहने, ब्राउन कलर के विग में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म में पूजा के प्रेमी, जिसमें अभिनेता राजपाल यादव भी शामिल हैं, उनके लहंगे से बाहर झांकते नजर आ रहे हैं. परेश रावल लहंगे का दूसरा सिरा पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में अन्नू कपूर स्तब्ध दिख रहे हैं. पोस्टर अपलोड करते हुए आयुष्मान ने लिखा, पूजाट्ठ ड्रीमगर्ल एक त्यौहार है, उसके आशिक हज़ार है! ड्रीमगर्ल2ट्रेलर अभी रिलीज! 25अगस्तहोगामस्त स ड्रीमगर्ल2, 25 अगस्त को सिनेमाघरों में.

1 अगस्त को इस अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. फिल्म करम के इर्द-गिर्द घूमती है जो महिला आवाज में गाने की अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूजा बन जाता है. आयुष्मान अनोखी पंचलाइन और विचित्रता के साथ किरदार में जान डाल देते हैं. दूसरी ओर, उन्हें फिल्म में अनन्या पांडे के किरदार से प्यार हो जाता है, जिसके पिता उसकी शादी करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं. दिलचस्प और मज़ेदार चुनौतियों से लेकर मुसीबत में फँसने तक, ट्रेलर एक मज़ेदार सवारी का वादा करता है.

छत्तीसगढ़ में भारतीय रेल का अनोखा खेल

» छत्तीसगढ़ की राजधानी में मुसाफिर बेहाल,लेकिन स्टेशन हो रहा मालामाल!

वृद्ध,विकलांग,छात्रों की सुविधा हटा दीं...

रायपुर, 11 अगस्त 2023(ए)। छत्तीसगढ़ में भारतीय रेल का ऐसा खेल चल रहा है कि एक तरफलचर रेल सेवा के कारण लाचार मुसाफिर बेहाल हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर अरबों रुपये न्यौछावर कर इन्हें मालामाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्टेशनों के उद्धार की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले समय में रेलवे स्टेशनों की शान एयरपोर्ट जैसी हो जाएगी। अच्छी बात है। विकास होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह विकास हो किसके लिए रहा है। जनता के धन पर रेलवे स्टेशन चकाचौंध पैदा करें और जनता को समय पर रेल नसीब न हो, कई कई घंटों की लेटलतीफी, रेल कैंसिल, जैसे तैसे रेल आ भी गई तो रास्ते-रास्ते कोयला गाड़ियों के सम्मान में उसे सिर झुका कर खड़े रहना है। मुसाफिर, मुकाम, मंजिल सब के सब परेशान हैं। ऐसे माहौल में आम जनता के दर्द को आवाज देना विपक्ष का काम है। छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस देश में विपक्ष में है तो छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र सरकार की रेल सेवा से हो रहे कष्ट पर आवाज बुलंद की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार रेलवे की अफ्लातूनी से छत्तीसगढ़ की जनता को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने हर स्तर पर हर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन कायाकल्प योजना पर मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस ने भी इसके औचित्य पर प्रहार किया है। सवाल यह है कि जब रेल ही नहीं रहेगी तो सुंदर स्टेशनों का क्या होगा? कांग्रेस का खुला आरोप है कि मोदी सरकार देश से रेलवे की यात्रा सुविधा को बंद करने का षड़यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेलवे को लेकर शंका जाहिर कर रहे हैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज कह रहे हैं कि रेलवे को लेकर मोदी सरकार की कार्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सुविधा परिवहन के निजीकरण का षडयंत्र रच रही है। मोदी सरकार ने देश की सबसे विश्वसनीय नागरिक परिवहन सुविधा मानी जानी वाली रेल सुविधा को मजाक बनाकर रख दिया है। वैसे आम तौर पर देखा जा रहा है कि पहले से आने जाने की तैयारी कर ट्रेन की टिकट आरक्षित कराने वाली जनता के साथ धोखा मोदी सरकार कर रही है। वैसे भी बीते 8 माह से अधिक हो चुका है जब ट्रेनों को अचानक स्थगित कर दिया जा रहा है। पहले की सरकारें रेलवे को नागरिकों की सुविधा के लिये चलाती थी, मोदी सरकार कमाने के लिये, जनता को लूटने के लिये रेलवे का इस्तेमाल कर रही है। रेल्वे ने जनता को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दीं। वृद्ध, विकलांग, छात्रों की सुविधा हटा दीं। रेल्वे स्टेशन पर टिकिट बिक्री बंद कर टिकिटों के दाम बढ़ा दिए। एक्सप्रेस ट्रेनों को गंतव्य स्थान पहुंचने के पहले बीच रास्ते में रद्द कर घोषणा कर दी जाती है कि ट्रेन आगे नहीं जायेगी। छत्तीसगढ़ की जनता रेलवे से तो त्रस्त है ही, उसे रेलवे की अव्यवस्था पर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों से भी निराशा है कि ये सब के सब वंदे भारत ट्रेन शुरू होने या स्टेशनों के तामझाम की योजना लॉन्च होने पर तो राजनीति की दुकान सजा लेते हैं लेकिन हर रोज छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों की बेतहाशा लेटलतीफी पर मौन धारण कर रखे हैं। त्यौहारों पर छत्तीसगढ़ में मेगा ब्लॉक लग जाता है। जनता परब मनाने नहीं जा पाती।भाजपा के 9 सांसदों की इस बेरुखी का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ रहा है।छत्तीसगढ़ की जनता की परेशानियों में कभी भी भाजपा के सांसद जनता के पक्ष में खड़े नहीं हुए। बीते कुछ महीनों से 2600 से अधिक ट्रेन बंद हुई थी, जिस के कारण छत्तीसगढ़ के रेलयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ट्रेन रद्द कर दी जाती है महीनों पहले यात्रा के लिए आरक्षित टिकटों को रद्द कर दिया जाता है और लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनबंदी हो रही है। 8 माह में छत्तीसगढ़ से चलने वाली और गुजरने वाली करीब 800 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है ट्रेन यात्री परेशान हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता रेल के इस खेल से तंग आ चुकी है।

हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की परीक्षा 26 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक

रायपुर, 11 अगस्त 2023(ए)। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित सितम्बर-अक्टूबर परीक्षा 2023 की समय-सारिणी का निर्धारण किया गया है, जिसमें हायर सेकेण्डरी की परीक्षा 26 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक और हाई स्कूल की परीक्षा 26 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगी। परीक्षा का समय प्रात 8.30 से 11.45 बजे तक निर्धारित किया गया है।राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने बताया कि छात्र-छात्राएं परीक्षा से संबंधित समय-सारिणी का समीपस्थ अध्ययन केन्द्र से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कार्यालय की वेबसाईट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. एसओएस.सीजी. एनआईसी. आईएन पर भी समय-सारिणी उपलब्ध है, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं।

इतने विधायकों को टिकट देना मुश्किल!

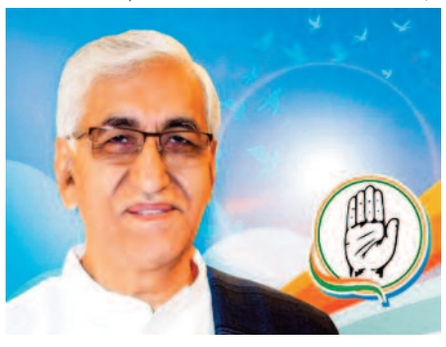

रायपुर, 11 अगस्त 2023(ए)। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। जिसमें मध्यप्रदेश का नाम भी शामिल है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इन दिनों मध्यप्रदेश दौरे पर हैं। मध्यप्रदेश में उन्होंने डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर कहा कि खास अंगूठी पहनने के बाद ही मुझे डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आगे मेरे साथ कुछ और बेहतर हो सकता है। वहीं, आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी, लेकिन कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। वहीं, उन्होंने मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनावी साल चल रहा है। सभी राजनेतिक पार्टियां अपने तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन इस बीच मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ के सभी 71 विधायकों को टिकट देना मुश्किल है। मेरे हिसाब से टिकट में कुछ चेंज होंगे। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा उसका टिकट नहीं बदलना जाएगा। कहा कि-'हमने सर्वे करवाया उसमें हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं'। सर्वे में सामने आया कि कौन मजबूत और कौन कमजोर है।

केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ से खरीदेगा चावल

रायपुर, 11 अगस्त 2023 (ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघले ने केन्द्र सरकार को चावल खरीदी को लेकर कई बार पत्र लिखा था उसके बावजूद केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने से मना कर दिया था। अब केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ से 86.5 लाख मीट्रिक धान खरीदने के लिए राजी हो गया।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने उनके सामने झोली फैलाकर चावल खरीदने की गुहार लगाई थी तब उन्होंने मना कर दिया था अब जरूरत पड़ी तो केन्द्र चावल खरीदने की बात कर रहे हैं। पहले 23 लाख मीट्रिक टन खरीदे फिर 26 लाख किए और बाद में 33 लाख मीट्रिक टन किया गया।

केन्द्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से देश में खाद्यान की कमी ना हो। अन्य देशो में गेहूं और चांवल की कमी हो गई इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें गेहूं और चांवल के निर्यात पर रोक लगाई गई थी।

अब्दुल जाहिद कुरैशी बने रायपुर के डीजे

» बलौदाबाजार, दंतेवाा के जिला जज भी बदले

» हाईकोर्ट ने 40 से ज्यादा जजों का किया तबादला, लिस्ट में उच्च न्यायिक सेवा व सिविल जज शामिल

बिलासपुर , 11 अगस्त 2023 (ए)। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश। ट्रांसफर आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। ट्रांसफर सूची में उच्च न्यायिक सेवा व सिविल जज शामिल हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर सिविल जजों का हुआ स्थानांतरण। प्रदेश के तीन जिला न्यायाधीशों के साथ ही न्यायिक सेवा के 40 से अधिक अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। इसके तहत रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ ही हाईकोर्ट के लीगल सेक्रेटरी, एडिशनल सेशन जज और सिविल जज शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अरविंद कुमार वर्मा ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर तबादला का आदेश जारी किया है।

अब्दुल जाहिद कुरैशी को रायपुर का डीजे, बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सूरजपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान को हाईकोर्ट में लीगल सेक्रेटरी बनाया है। रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा, रायपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी, अंबिकापुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल, बलौदाबाजार के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन कुरेशी, कवर्धा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु जैन, कोंडागांव के प्रथम सिविल न्यायाधीश मोना चौहान, राजनांदगांव के प्रथम सिविल न्यायाधीश प्रियंका अग्रवाल, मुंगेली के तृतीय व्यवहार न्यायाधीश लोकेश कुमार और बैकुंठपुर सिविल जज क्लास 2 वीरेंद्र सिंह का नाम तबादला लिस्ट में है।

12 अगस्त

स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष
सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष,
आरटीआई एक्टिविस्ट, समाजसेवी एवं अधिवक्ता

श्री डी.के. सोनी जी

को जन्मदिवस की

हार्दिक शुभकामनायें

राकेश सोनी
प्रदेश महासचिव
स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन (छ.ग.)

अखिलेश सोनी
प्रदेश कोषाध्यक्ष
स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन (छ.ग.)

श्रीमती नीलम सोनी
प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग
स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन (छ.ग.)

राजू सोनी
प्रदेश संगठन मंत्री
स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन (छ.ग.)

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No. CHHHIN/2004/15050,मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)